राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 326 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार, 03 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा वैक्सीन का पूरा हिसाब

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि वह अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के संबंध में विस्तृत विवरण मुहैया कराए। अदालत ने केंद्र से कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक श तीनों की वैक्सीन के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो विवरण मांगा है उसमें तीनों ही 1/ वैक्सीन की खरीद की तारीख, 2/ हर तारीख में खरीदी गई वैक्सीन की संख्या और 3/ वैक्सीन की सप्लाई की संभावित तारीख की जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से ये भी पूछा है कि वह 1, 2 और 3 चरण में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करेगी,

अदालत ने इसका भी पूरा विवरण मांगा है।

इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि वह म्यूकरमाइकोसिस की दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। देश में कोविड -19 से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दायर एक स्वतः संज्ञान मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की खंडपीठ द्वारा यह फैसला जारी किया है। इसमें कहा गया कि एफिडेविट फाइल करते समय भारत सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जरूरी दस्तावेजों की कॉपियां और फाइल नोटिंग्स उसकी सोच को दशार्ती हैं और वैक्सीनेशन पॉलिसी में अंतिम परिणाम तक पहुंच रही हैं और उसकी टीकाकरण नीति में साफ स्पष्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण पर केंद्र की नीति को मनमाना और तर्कहीन बताते हुए कहा कि वर्तमान में उस आयु वर्ग के लोग न केवल संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु सहित संक्रमण के गंभीर प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं।

चोकसी की पत्नी ने कहा- पति का हो सकता है मर्डर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पंजाब नेशनल बैंक में 13500 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का फैसला हो सकता है। इस बीच, उसकी पत्नी प्रीति चोकसी ने मेहुल की जान को खतरा बताया है। प्रीति ने डोमिनिका के समुद्र तट पर चोकसी के साथ याट में देखी गई लड़की को लेकर भी जानकारियां दी हैं। प्रीति चोकसी ने कहा उनके पति 23 मई की शाम को रात के खाने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद वह कभी नहीं लौटे।

प्रीति ने बताया कि उन्होंने चोकसी का पता लगाने के लिए समुद्र तट पर एक सलाहकार और रसोइए को भेजा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर आखिरकार पुलिस से संपर्क किया। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने कहा मैं ये जानकर परेशान हो गई थी कि चोकसी को शाम लगभग 5।30 बजे एक याट पर ले जाया गया और किसी ने यह नहीं देखा।

यही नहीं, उनकी कार भी मौके से गायब थी, जिसे अगली सुबह तीन बजे इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने बरामद किया। जब प्रीति से मिस्ट्री गर्ल बारबरा जैबरिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया मैं जानती हूं कि जैबरिका पिछले साल अगस्त में एंटीगा आई थी। वह आइलैंड में हमारे दूसरे घर पर भी आ चुकी है। वहां के शेफ से उसकी दोस्ती हो गई थी। बारबरा को चोकसी की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है।

प्रीति ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया के उन दावों का भी खंडन किया कि जैबरिका सेक्सी फीमेल फेटेल थी। उन्होंने बताया बारबरा अलग दिखती है, पर वह वैसी नहीं है जैसी कि दिखती है। उसके पास एक अच्छा शरीर हो सकता है, जो भी हो, बात यह है कि यह उसकी तस्वीर नहीं है।

प्रीति चोकसी ने कहा कि उनके पति ने खराब स्वास्थ्य के कारण तीन साल तक आईलैंड नहीं छोड़ा था। उसने आरोप लगाया कि उन्हें एक वकील से मिलने या मेडिकल सुविधा लेने की भी अनुमति नहीं थी। ऐसे में उसे डर है कि उसके पति को मार दिया जाएगा। प्रीति चोकसी ने कहा मीडिया में कहानियां बनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि चोकसी फरार हो गया है। प्रीति ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 9 के अनुसार मेरे पति अब भारतीय नागरिक नहीं हैं। 2017 में वह एंटीगा की नागरिकता ले चुके हैं। उनके लिए धरती पर सबसे सुरक्षित जगह एंटीगा है।

डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉ. हर्षवर्धन का कार्यकाल पूरा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉ. पैट्रिक अमोथ को डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

डब्ल्यूएचओ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया है। दरअसल हर साल यह सम्मान दिया जाता हैं, जो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कारों के नाम से जाना जाता है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक अधनम टेड्रोस ने ट्वीट कर कहा कि तंबाकू के लिए विशेष मान्यता के साथ डॉ. हर्षवर्धन को पुरस्कृत करते हुए खुशी हो रही है। ई-सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में उनका योगदान उल्लेखनीय है।

कोरोना से जीत रहे जंग, चला गया पीक : केंद्र

नई दिल्ली। भारत से कोरोना का प्रकोप कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद कुछ राहत की खबर आई है। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि लगभग आधें भारत में अब केवल 5 प्रतिशत सकारात्मकता दर दर्ज की रही है। केंद्र ने यह भी कहा कि देश से कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब जा चुका है और कोरोना का ट्रांसमिशन अब काफी हद तक स्थिर हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा, आज लगभग 350 जिलों में 5 प्रतिशत से कम पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला है और 145 जिलों में 5 से 10 प्रतिशत तक सकारात्मक दर देखी जा रही है। हालांकि, अभी भी 10% से अधिक सकारात्मकता वाले 239 जिले हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी आयोजित किए गए सभी टेस्टों में से आए कुल पॉजिटिव नतीजों का प्रतिशत है । यह समुदाय के भीतर ट्रांसमिशन के स्तर को निर्धारित करने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि किसी संक्रमण के दौरान उसका पॉजिटिविटी रेट लगातार दो हफ्तों तक 5 प्रतिशत के अंदर रहता है तो ऐसे में ट्रांसमिशन को स्थिर कहा जा सकता है। केंद्र ने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 200 से कम जिलों में 10% से अधिक सकारात्मकता थी। अप्रैल के अंत तक, यह संख्या लगभग 600 जिलों तक पहुंच गई थी। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं परीक्षण तेजी से बढ़े हैं और साथ ही जिला स्तर पर काम किया गया है. हालांकि, यह एक स्थायी समाधान नहीं है, हमें अपनी रोकथाम, लॉकडाउन को , कंटेनमेंट जोन को बहुत धीरे-धीरे खोलना होगा। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पॉल ने कहा, कोरोना के पीक को गुजरे कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है पर हमें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालम करना है और कोविड-उपयुक्त व्यवहार करना है।

पवार और फडणवीस के बीच बैठक, शिवसेना ने कहा इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेन्द्र फडणवीस के बीच हालिया बैठक को तवज्जो नहीं देकर कहा कि बैठक में कुछ भी गोपनीय नहीं है, क्योंकि राकांपा प्रमुख का ऐसा व्यक्तित्व है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेता विभिन्न मुद्दों पर उनकी सलाह लेते रहते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में इन कयासों को भी खारिज कर दिया गया कि सोमवार की बैठक के बाद ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल होगी।

संपादकीय में लिखा गया है, फडणवीस और पवार के बीच हाल में हुई बैठक में कोई गोपनीयता या रहस्य नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है, वे शरद पवार को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। फडणवीस ने सोमवार की सुबह मुंबई में शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि सर्जरी से ठीक होने के बाद पवार (80) के साथ यह शिष्टाचार मुलाकात थी। शिवसेना महाविकास आघाडी (एमवीए) सरकार का नेतृत्व कर रही है,जिसमें राकांपा और कांग्रेस भी शामिल हैं। संपादकीय में कहा गया कि पवार आराम करने में विश्वास नहीं करते हैं और उनके समर्थक एवं आलोचक उन्हें व्यस्त रखते हैं। लेकिन राजनीति गलियारों में चर्चा शुरू हो गई की महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बहरहाल, फडणवीस ने जो कहा वह सच है। यह पूरी तरह शिष्टाचार मुलाकात थी।

पवार न केवल महाराष्ट्र के नेता हैं बल्कि वह पूरे देश के नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम नेता उनसे विभिन्न मुद्दों पर सलाह लेते हैं। शिवसेना ने इंदिरा गांधी और समाजवादी नेता जय प्रकाश नारायण की मुलाकात का जिक्र कर कहा कि कुछ नेताओं का व्यक्तित्व राजनीति से ऊपर होता है जैसा कि पवार का है। शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में कई नेता पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात करने आते थे।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: निर्माण को हरी झंडी देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली । सेंट्रल विस्टा का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास गतिविधियों को रोकने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह अपील अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने दायर की है। दिलचस्प बात यह है कि यादव, दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे।

याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह कहना भी उचित नहीं था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमिक परियोजना स्थल पर रह रहे हैं जबकि सरकार और एसपीसीपीएल (प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी) ने अपने-अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा था कि श्रमिक सराय काले खां के कैंप में रह रहे थे, जो परियोजना स्थल नहीं है।

सराय काले खां से मजदूरों व पर्यवेक्षकों को लाने और ले जाने के लिए आवाजाही पास जारी किया गया था। गत वर्ष 20 मार्च को केंद्र ने 20 हजार करोड़ की परियोजना के लिए लैंड यूज में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जो मध्य दिल्ली में 86 एकड़ भूमि से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय जैसी इमारतें शामिल हैं।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गत पांच जनवरी को लैंड यूज और पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना के चलते निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा था कि यह राष्ट्रीय महत्व की एक अहम और आवश्यक परियोजना है। इसके साथ ही अदालत ने इस परियोजना के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह किसी मकसद से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण थी।पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा कि वह इस दावे से असहमत है कि यह परियोजना आवश्यक गतिविधि नहीं है और इसलिए, मौजूदा महामारी के दौरान इसे रोक दिया जाना चाहिए।

सत्र न्यायालय के फैसले पर बांबे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, तरुण तेजपाल को भेजा नोटिस

पणजी। बांबे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार को पत्रकार तरुण तेजपाल मामले में सत्र न्यायालय के फैसले पर कठोर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि तरुण तेजपाल को बरी करने का सत्र अदालत का फैसला दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए एक नियम पुस्तिका जैसा है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि किसी पीड़िता को ऐसे मामलों में कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जस्टिस एससी गुप्ते ने तेजपाल को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 24 जून तय की है।

गोवा सरकार ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक की रिहाई को उच्च न्यायालय में दी है चुनौती - हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज को सत्र अदालत से मंगवाने का भी निर्देश दिया है। गोवा सरकार ने तेजपाल की रिहाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गुप्ते ने कहा, यह फैसला इसे लेकर है कि उसने (पीड़िता ने) कैसी प्रतिक्रिया दी है। इसी पर गौर किया गया है। यह दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए नियम पुस्तिका जैसा है। फैसला सीधे मामले के सार और उसके बाद पीड़िता के साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए दिया गया। यह पहली नजर में रिहाई के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करने का मामला लगता है।

गोवा सरकार का पक्ष रख रहे सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सत्र अदालत के 527 पन्नों के फैसले के कुछ हिस्सों को पढ़ा, जिसमें पीड़ता के व्यवहार (कथित घटना के दौरान और बाद में) का जिक्र किया गया है। बता दें कि सत्र अदालत की न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को इस मामले में 21 मई को बरी कर दिया था। तेजपाल पर नवंबर, 2013 में गोवा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उस वक्त सहयोगी रही एक महिला से पांच सितारा होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे थे।

कार्टून

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए।

सीबीएसई के बाद कई राज्यों में रद हुई 12वीं की परीक्षाएं

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के बाद कई राज्यों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वालों में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान व गोवा शामिल हैं। हालांकि, हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं रद करने के निर्णय पर कानूनी मुहर मंत्रिमंडल की बैठक में लगेगी। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद करने का निर्णय लिया गया था। इसके एक दिन बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की हायर सेकंडरी की परीक्षा रद कर दी गई है। बता दें कि मंगलवार को परीक्षा रद करने की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अब राज्यों के पास भी 12वीं परीक्षा रद करने का विकल्प होगा।। हालांकि 12वीं परीक्षा रद किए जाने को लेकर राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसे में अब कई स्टेट बोर्डों द्वारा परीक्षाए रद किए जा रहे हैं।

राजस्थान में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा ना कराने का निर्णय लिया गया है। छात्रों के हित को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इधर, गोवा में भी 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद करने की घोषणा की है।

उत्तराखंड में अब 12वीं की परीक्षाएं भी रद हो गई। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक देश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर जो निर्णय हुआ है। राज्य सरकार उस फैसले से बाहर नहीं हैं। परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा रद करने का फैसला किया गया।

मध्य प्रदेश की राज्य बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष अयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए अनमोल है। करियर की चिंता हमलोग बाद में कर लेंगे। बच्चों पर जिस समय कोरोना का बोझ है, उस समय हम उन पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ नहीं डाल सकते।

उन्होंने कहा कि 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस आधार पर तैयार किए जाएंगे ये तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर विचार करेंगे और रिजल्ट का तरीका तय करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को न कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा।

कोरोना संकट को देखते हुए गुजरात सरकार ने बच्चों को एक बड़ी राहत दी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद अब गुजरात बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद कर दी है। गुजरात सरकार ने बुधवार को 12वीं की परीक्षा रद करने का आदेश जारी किया। इससे पहले गुजरात कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा को रद करने पर आम सहमति बनी।

सार समाचार

पाकिस्तान में हिंदू कारोबारी की हत्या पर विरोध प्रदर्शन, कराची को जोड़ने वाली सड़क पर घंटों जाम

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के व्यापारियों ने एक हिंदू व्यापारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की वजह से खुजदार और कराची के बीच कई घंटों तक जाम लगा रहा। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, खुजदार और कराची के बीच कई घंटों तक यातायात बाधित रहा, जबकि व्यापारियों ने सोमवार को एक हिंदू व्यापारी की हत्या के खिलाफ बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वाध शहर में पूरी तरह बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हथियारबंद लोगों ने वाध बाजार में अशोक कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यापारी पर उस समय गोलियां चला दीं, जब वह अपनी दुकान पर बैठे थे। इससे कुमार को चोटें आई हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल वाध ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हिंदू व्यापारी की हत्या की सूचना मिलते ही वाध के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और खुजदार और कराची के बीच यातायात को बाधित करते हुए बैरिकेड्स लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी-मंगल) के रक्षक व्यापारियों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है।

सैमसंग के बॉस को रिहा करने की सिफारिश, उद्योगपतियों ने की कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात

सियोल। दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों के एक समूह ने जेल में बंद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन जे वाई. ली को जेल से रिहा करने की सिफारिश की है। उद्योगपतियों ने एक औपचारिक लंच के दौरान देश के राष्ट्रपति मून जे-इन से यह सिफारिश की। राष्ट्रपति से कहा गया कि जे वाई. ली को जेल से रिहा करना करना चाहिए, क्योंकि यह चिप उद्योग में देश की बढ़त बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम है। दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी चिप निर्माता और दूसरे सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट चिप निर्माता सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन जे वाई. ली को रिश्वत, गबन और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें 30 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति मून की प्रवक्ता पार्क क्यूंग-मी के मुताबिक, एसके ग्रुप के चेयरमैन चे ताए-वोन ने राष्ट्रपति मून से अप्रैल के महीने में रिहाई के लिए दी गई संयुक्त याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। बता दें कि अप्रैल के महीने में ये संयुक्त याचिका कोरिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत पांच बिजनेस लॉबी द्वारा दी गई थी। प्रवक्ता पार्क के एक बयान के मुताबिक, 'राष्ट्रपति मून ने कहा है कि वो कंपनियों की दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले वो जनता की राय जानना चाहते हैं, इसके बाद ही वो कोई फैसला लेंगे।'

रसायनों से भरे इस मालवाहक जहाज से श्रीलंका के समुद्री इलाके में दशकों बाद पर्यावरण को गंभीर खतरा, चिंतित हुई दुनिया

कोलंबो, एजेंसियां। श्रीलंका के पश्चिमी समुद्र तट पर एक जहाज आग लगने के बाद डूब रहा है। रसायनों से भरे इस मालवाहक जहाज से श्रीलंका के समुद्री इलाके में दशकों बाद गंभीर पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया है। हादसे में कम नुकसान के लिए भारतीय दल भी सहायता कर रहे हैं। सिंगापुर में पंजीकृत एमवी एक्सप्रेस पर्ल नाम के इस जहाज में 25 टन नाइट्रिक एसिड के साथ ही 1486 कंटेनर लदे हुए हैं।

जहाज में 20 मई को लगी थी आग

यह पश्चिमी तट पर रुका हुआ था, तभी इसमें 20 मई को आग लग गई थी। नौसेना ने कहा कि हम आग से जूझ रहे हैं, इसमें लदे रसायनों वाले कंटेनर जहाज के डेक से गिर गए हैं। अब जहाज का पिछला हिस्सा तेजी से डूब रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कई दशकों के बाद सबसे बड़ा हादसा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर संकट हो गया है। इसने मछली पकड़ने वाले समृद्ध क्षेत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

ईरान को बड़ा झटका, नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूबा

दुबई, एजेंसियां। इजरायल के साथ बेहद तनावपूर्ण संबंधों के बीच ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया। लगातार बीस घंटे तक आग पर काबू पाने का प्रयास किए जाने के दौरान चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह घटना ईरानी बंदरगाह जास्क के पास हुई है। आग लगने के कारण पर अभी रहस्य बना हुआ है।

इजरायल से तनाव के बीच ईरान को बड़ा झटका

ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार खर्ग युद्धपोत में आग स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार को देर रात 2.25 बजे लगी। यहां पर युद्धपोत पर अभ्यास चल रहा था। ओमान की खाड़ी होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ती है। यह स्थान तेहरान से लगभग 1270 किमी. दूर है। ईरान के सबसे बड़े इस युद्धपोत को बचाने के सभी प्रयास बेकार साबित हुए। लाइफ जैकेट पहने चालक दल के सदस्यों को बाहर निकालते हुए वीडियो ईरान में वायरल हो रही है। चालक दल सदस्यों के पीछे जहाज में भयंकर आग लगी दिखाई दे रही है।

इजरायल में एकजुट हो रहे विपक्षी दल, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अहम है आज का दिन

यरूशलम। (एजेंसी)।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बुधवार का दिन अहम है। देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और संसद नेसेट में 120 सांसद नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए मत डालेंगे। वहीं विपक्षी दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए बुधवार को बहुमत होने की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल इसाक हेरजोग वरिष्ठ राजनेता हैं और इजरायल के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं जबकि दूसरे उम्मीदवार मिरियम पेरेत्ज शिक्षाविद हैं। हेरजोग (60) इजरायल की लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता हैं। 2013 के संसदीय चुनाव में वह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए थे लेकिन हार गये थे। पेरेत्ज (67) राष्ट्रवादी विचारधारा की हैं। यदि वह चुनाव जीत जाती हैं तो इस पद की शोभा बढ़ाने वाली पहली महिला होंगी। जिस भी उम्मीदवार को 120 सदस्यीय नेसेट में कम से कम 61 मत मिल जाएंगे वह जीत जाएगा। चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार देश का 11वां राष्ट्रपति बनेगा और उसका सात साल का कार्यकाल नौ जुलाई से आरंभ होगा। वर्तमान राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन अगले महीने पद छोड़ने वाले हैं। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोधी बुधवार को उनके 12 साल के शासन को समाप्त करने के लिए एक गठबंधन सरकार के गठन की मशक्कत कर रहे हैं। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। मध्यमार्गी विचारधारा के येर लापिद और अति राष्ट्रवादी माने जाने वाले नाफ्ताली बेनेट ने गठजोड़ किया है और बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने को सहमत हुए हैं। वे अन्य दलों को भी शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इजरायल के मीडिया के अनुसार निचले स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कुछ असहमतियां हैं, लेकिन लापिद बुधवार को किसी भी वक्त गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। उनके पास इजराइल के निवर्तमान राष्ट्रपति रिवलिन को सूचित करने के लिए मध्यरात्रि तक का समय है। उन्हें सूचित करना है कि उनके पास नेसेट में कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन है। इसके बाद उन्हें विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर लापिद मध्यरात्रि की समयसीमा तक राष्ट्रपति को सूचित नहीं कर पाते तो देश में दो साल के भीतर ही पांचवीं बार चुनाव की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में नेतन्याहू को पद पर बने रहने का एक और मौका मिल जाएगा, जो भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

अफगान शांति मसले पर बैठक करेंगे चीन, पाक व अफगानिस्तान के विदेश मंत्री

बीजिंग (एजेंसी)।

अफगान शांति प्रक्रिया पर चर्चा के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी करेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मद्देनजर चीन इन दोनों देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूती दे रहा है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि वांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की चौथी त्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार हिस्सा लेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि तीनों विदेश मंत्री अफगान शांति एवं सुलह प्रक्रिया, व्यावहारिक सहयोग, आतंकवादरोधी एवं सुरक्षा सहयोग के मद्देनजर विचार साझा करेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को देखते हुए पिछले महीने चीन ने शांति बनाए रखने को लेकर अफगान सरकार और तालिबानी आतंकियों के बीच वार्ता की मेजबानी करने की पेशकश की थी।

भारत में लगे लॉकडाउन से बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के साथ कम हुआ जमीन की सतह का तापमान

लंदन। (एजेंसी)।

कोरोना महामारी के कारण पिछले साल भारत में लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से वायु प्रदूषण तो कम हुआ ही, उसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि बड़े शहरों में जमीन की सतह का तापमान भी कम हुआ। यह निष्कर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन (यूके) और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के शोध से निकला है। शोधकर्ताओं की टीम ने अपने अध्ययन में अर्थ आब्जर्वेशन सेंसर के डाटा का इस्तेमाल किया है।

भारत के छह प्रमुख शहरों का किया गया अध्ययन

इसमें पिछले साल मार्च से मई के महीने में भारत के छह प्रमुख शहरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में जमीन की सतह का तापमान, वायु प्रदूषण और एयरोसोल की स्थिति में आए बदलाव का आकलन किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि देशभर में वातावरण में नाइट्रोजन डाइआक्साइड की मात्रा में औसतन 12 फीसद कमी आई, जबकि इन छह शहरों में यह आंकड़ा 31.5 फीसद रहा। यह भी पाया कि इन शहरों में पिछले पांच वर्षों (2015-2019) की तुलना में लैंड सरफेस टेंपरेचर (एलएसटी) में दिन में औसतन एक डिग्री और रात में दो डिग्री तक की कमी आई। शोधकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 40 फीसद की कमी आई है।

प्रतिबंधों के कारण हुआ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार

अध्ययन में पाया गया कि कोरोना महामारी की शुरुआत में लगाए गए यात्रा और कार्य प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक गतिविधियों में अचानक कमी और भूमि और हवाई परिवहन के उपयोग में बड़ी कमी के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार हुआ।

शोधकर्ताओं ने सतह के तापमान और वायुमंडलीय प्रदूषकों और एरोसोल में परिवर्तन को मापने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटीनेल -5 पी और नासा के मोडिस सेंसर सहित पृथ्वी अवलोकन सेंसर की एक श्रृंखला से डेटा का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि अकेले भारत में खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आने के कारण सालाना लगभग 16,000 लोगों की अकाल मौतें होती हैं।

चीन के खिलाफ आवाज उठाने की ब्लॉगर को मिली सजा, गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या पर उठाए थे सवाल

बीजिंग। (एजेंसी)।

चालबाज चीन अपनी गलतियां छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ड्रैगन ने एक बार फिर ऐसी ही चालाकी चली है। जिसमें उसने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया कानून बना दिया है। चीनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में बंद किया जा रहा है। दरअसल, पिछले साल भारत के साथ गलवान घाटी में झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर एक चीनी ब्लॉगर ने संदेह जताया था। जिसके बाद उसे चीनी सरकार ने एक नए कानून के तहत आठ महीने के लिए लेज की सजा सुना दी है। गौरतलब है कि पिछले साल जून के महीने में गलवान घाटी में एलएसी पर भारत और चीनी सेना के जवानों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। झड़प में चीन के चालीस से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने की जानकारी मिली थी। लेकिन चीन ने कभी इस आंकड़ों को कबूला नहीं था।

चीनी सेना ने फरवरी में कहा था कि उनके केवल चार सैनिक ही शहीद हुए हैं। जिसके बाद चीन के सेना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के फेमस ब्लॉगर चाउ जेमिंग ने फरवरी में ही दो वीडियो पोस्ट किये थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी अधिकारियों के जरिये घोषित चार मौतों की जगह चीनी सेना को सीमा संघर्ष में भारी हताहतों का सामना करना पड़ा होगा। इसके बाद चाउ को मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें चीनी नायकों और शहीदों को बदनाम करने का दोषी पाया गया है। वहीं चाउ जेमिंग को अदालत ने मार्च में पारित किए गए नए सुरक्षा कानून के तहत दोषी बनाया।

ब्लॉगर को हुई 8 महीने की सजा

ब्लॉगर को सजा देने के साथ ही इसे राष्ट्रीय मीडिया के जरिये 10 दिनों के भीतर अपने बयान के लिए माफी मांगने का भी आदेश दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चाउ ने अपनी गलती स्वीकार की है और अदालत में अपनी मर्जी से कहा है कि वह आगे कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इसलिए उसे कम सजा दी गई है। इससे पहले 1 मार्च को चाउ जेमिंग की तरफ से टीवी चैनल पर आकर अपने बयान के लिए माफी मांगी गई थी।

सिंगापुर में हवाई यात्रियों के लिए संक्रमित नहीं होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य

बीजिंग। (एजेंसी)।

सिंगापुर। सिंगापुर के अधिकारियों ने विमानन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि देश में आने वाले यात्री विमान में सवार होने से पहले कोरोना वायरस जांच की वैध रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ÷चैनल न्यूज एशिया÷ की खबर में बताया गया कि यह नियम सिंगापुर के नागरिकों और स्थायी निवासियों पर भी लागू होगा। इससे पहले केवल दीर्घकालीन पास धारकों और कम वक्त के लिए आने वाले आगंतुकों को कोविड-19 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) जांच रिपोर्ट देने की जरूरत थी, जिसमें उनके संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हो।

इन नये निर्देशों से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि सिंगापुर के नागरिकों और स्थायी निवासियों को अब देश में आने वाली उड़ानों के प्रस्थान से 72 घंटे पहले कराई गई जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। सिंगापुर के नागर विमानन प्राधिकरण के सुरक्षा निदेशक मार्गरेट टैन ने कहा, 'विमानन कंपनियों को सिंगापुर आने वाली उड़ान में सवार होने की किसी भी ऐसे यात्री को अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो जरूरी पीसीआर जांच की रिपोर्ट न प्रस्तुत करे या पीसीआर जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव हो।

टैन ने कहा कि ये पीसीआर प्रमाण-पत्र सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, क्लीनिक या अस्पताल से जारी होनी चाहिए। यहां चांगी हवाईअड्डे तक उड़ान सेवाओं का परिचालन करने वाली सभी विमानन कंपनियों को नये नियम से अवगत करा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जो लोग वैध नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आएंगे, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता है। उसने साथ ही कहा कि जो स्थायी निवासी और दीर्घकालिक पास धारक इसका अनुपालन नहीं करेंगे, उनके परमिट या पास भी रद्द किए जा सकते हैं। आव्रजन एवं जांच बिंदु प्राधिकरण (आईसीए) की सेफ ट्रैवल वेबसाइट के मुताबिक, विमान या नौका से यात्रा करने वाले लोगों को सिंगापुर में आगमन पर हवाई या समुद्री जांच केंद्रों पर जांच परिणाम प्रस्तुत करेंगे।

इस बीच, सिंगापुर एयरलाइन्स ने कहा कि यात्रियों को उनके सेवा एजेंटों को वैध नेगेटिव जांच प्रमाण-पत्र दिखाना होगा। खबर में विमानन कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, 'जो यात्री वैध प्रमाण-पत्र नहीं दिखा पाएंगे उन्हें विमान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।' हालांकि, विमानन कंपनी ने कहा कि जो समय से कोविड-19 जांच नहीं करवा पाएंगे उन्हें बिना किसी जुर्माने के दूसरी उड़ान के लिए बुकिंग करने की अनुमति होगी।

ईरानी नौसेना का ताकतवर जहाज आग के बाद ओमान की खाड़ी में समाया, जांच में जुटे अधिकारी

तेहरान। ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज खर्ग आग लगने के बाद बुधवार को ओमान की खाड़ी में डूब गया। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक नौसेना के इस जहाज को बचाने के सभी प्रयास नाकाम रहे। जानकारी के मुताबिक नौसेना के जहाज में आग देर रात 2.25 बजे लगी, तब से ही दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना ओमान की खाड़ी में तेहरान से करीब 1,270 किलोमीटर दूर दक्षिणपूर्व में स्थित जस्क बंदरगाह के पास हुई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

सोशल मीडिया पर डूबते हुए नौसेना के जहाज की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीरों में लाइफजैकेट पहने नौसैनिकों को जहाज को निकालते हुए देखा जा सकता है। साथ ही तस्वीरों में जहाज में लगी आग और धुएं को भी देख सकते हैं। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल खर्ग को एक 'प्रशिक्षु जहाज' बता रहे हैं। खर्ग जहाज का ईरान की नौसेना में बहुत महत्व था। उधर, नौसेना के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जहाज में किन कारणों से आग लगी। इसको लेकर ईरान की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। खर्ग जहाज का डूबना ईरान के लिए बड़ा हादसा है। साल 2020 में ईरानी सेना के अभ्यास के दौरान जस्क बंदरगाह के पास ही एक मिसाइल गलती से नौसेना के जहाज से टकरा गई थी, जिससे 19 सैनिकों की मौत हो गई थी और 15 सैनिक घायल हो गए थे।

सीरिया को सहायता पहुंचाने के सिलसिले में तुर्की रवाना हुईं अमेरिकी राजदूत

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड यह सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार देर रात तुर्की रवाना हुईं कि विभिन्न सीमाओं से सीरिया तक मानवीय सहायता पहुंचायी जाए। दरअसल, रूस ने केवल एक सीमा से मानवीयता सहायता पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सीरिया सरकार को लाखों जरूरतमंदों को दी जाने वाली हर तरह की सहायता पर नियंत्रण रखना चाहिए।

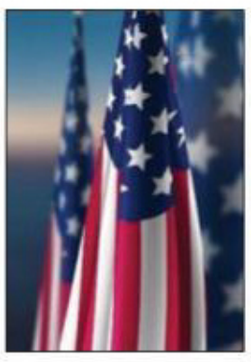

ग्रीनफील्ड की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आदेश की अवधि 10 जुलाई को समाप्त हो रही है। अब यह मानवीय सहायता तुर्की से सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिम हिस्से में केवल एक सीमा से पहुंचायी जा रही है। यह सब सीरिया के करीबी सहयोगी रूस के दबाव के चलते हुआ। यह यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के 14 जून को ब्रसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन के इतर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के साथ पहली मुलाकात के मद्देनजर हो रही है। एक समय रणनीतिक साझेदार माने जाने वाले तुर्की और अमेरिका के बीच रिश्ते हाल के वर्षों में बिगड़ गए हैं। उनके बीच सीरिया, रूस के साथ तुर्की के सहयोग और पूर्वी भूमध्यसागर में तुर्की के नौसैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी मतभेद हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के मिशन ने मंगलवार को घोषणा की कि ग्रीनफील्ड बुधवार से शुक्रवार तक तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर ''अमेरिका-तुर्की संबंध मजबूत करने, वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सीरिया के मामले पर सहयोग बेहतर बनाने को लेकर हमारे नाटो सहयोगी के साथ काम करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी''।

सेना का अपमान करने के आरोप में घिरे पाकिस्तानी पत्रकार को अधिकारियों ने तलब किया

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने मंगलवार को बताया कि उन पर प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान का अपमान करने के आरोप लगने के बाद अधिकारियों ने उन्हें तलब किया है। सेना को अकसर प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है। 'आज न्यूज पाकिस्तानी' टीवी चैनल के लिए काम करने वाले असद अली तूर ने कहा कि वह अपने वकील से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें चार जून को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने तूर के घर में घुसकर उन्हें पीटा था। वे लोग खुद को 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई)' का बता रहे थे।

हमलावरों ने तूर को कई थप्पड़ मारे थे और उन पर एजेंसी का अपमान करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि आईएसआई ने कहा था कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि अधिकारी तूर पर हमला करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन तूर का कहना है कि वह सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। तूर ने 'एपी' को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हमलावरों में से एक ने उनके हाथ और पैर बांधने के बाद पिस्तौल से कई बार उनकी भुजाओं पर वार किया। तूर ने कहा, '' जब हमलावरों में से एक ने मेरे सिर पर पिस्तौल रखी तो मुझे लगा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी।'' उन्होंने बताया कि उनके समर्थन में बात करने वाले उनके साथी पत्रकारों को भी परेशान किया जा रहा है। तूर ने बताया कि उनमें से एक मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर हैं, जिन्हें शुक्रवार को एक रैली में सेना विरोधी भाषण देने के लिए पाकिस्तान के 'जियो न्यूज टीवी' पर उनके मशहूर शो से बाहर कर दिया गया था।

मीर ने मंगलवार को 'एपी' से कहा कि उन्होंने सेना के खिलाफ शायद ''कड़े शब्दों'' का इस्तेमाल किया लेकिन उनका भाषण देश में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों की प्रतिक्रिया था। उन्होंने कहा कि वह रैली में तूर और उन पत्रकारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए गए थे, जिन पर हाल ही में हमले किए गए। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, लेकिन मानवाधिकार समूह पाकिस्तानी सेना और उसकी एजेंसियों पर अकसर पत्रकारों को परेशान करने तथा उन पर हमले करने का आरोप लगाते रहे हैं।

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की प्रमुख हिना जिलानी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में तूर पर हमले, मीर को टीवी शो से निकालने और अन्य पत्रकारों पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, '' पत्रकारिता कोई अपराध नहीं है। असहमति कोई अपराध नहीं है।

नोएडा में अवैध शराब का भंडाफोड़ पुलिस ने 11 तस्करों को किया गिरफ्तार

नोएडा, (एजेंसी)। नोएडा में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 11 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मंगलवार रात को एक सूचना के आधार पर रोहित तथा अखिल हलदर को गिरफ्तार किया और उनके पास से 90 पौव्वा शराब बरामद किया है। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस ने सेक्टर 73 के पास से सकलेन नामक युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास से 40 पौव्वा हरियाणा मार्का शराब बरामद की। प्रवक्ता ने बताया कि थाना सेक्टर 39 पुलिस ने शीशपाल तथा जीवन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 70 पौव्वा शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि थाना बादलपुर पुलिस ने 46 पौव्वे शराब बरामद की और इस मामले में रवि शर्मा को गिरफ्तार किया। थाना बादलपुर पुलिस ने ही नीरज नामक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 32 पौव्वा शराब बरामद की। इसके अलावा थाना दादरी पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर उसके पास से 30 पव्वा हरियाणा मार्का शराब बरामद की। उन्होंने बताया कि थाना फेस -2 पुलिस ने मनोज तथा जितेंद्र सिंह नामक दो शराब तस्करों को भूड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया और उनके पास से 100 पव्वा शराब बरामद की। थाना इकोटेक- प्रथम पुलिस ने शशिकांत नामक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 42 पव्वा अवैध देसी शराब बरामद की।

देश में पहली बार कर्मचारी वेतन के लिए निगम को बेचनी पड़ेगी संपत्ति : सिसोदिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि किसी नगर निगम को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के नगर निगम कई महीनों से अपने कमर्चारियों को वेतन देने में नाकाम रही है इसलिए कोर्ट ने निगमों को फटकार लगाते हुए कहा है कि निगम अपनी संपत्तियां बेच कर कर्मचारियों को वेतन दे। सिसोदिया ने इसे भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के लिए काफी शर्मनाक बताया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम आज एक अभूतपूर्व संकट में है। पिछले 20 सालों से दिल्ली के लोगों ने भरोसा करके भाजपा को नगर निगम का शासन सौंपा लेकिन भाजपा ने सिर्फ लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। भाजपा ने निगम में काम करने की जगह उसे बदहाल कर दिया है। इसलिए दिल्ली के निगमों को आज एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ रहा है जैसा देश में पहले किसी और नगर निगम को नहीं करना पड़ा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमेशा निगमों को समय पर और ज्यादा फंड दिया साथ ही लोन और ब्याज राशि के भुगतान को भी एडजस्ट किया लेकिन उसके बाद भी निगम की हालत बदहाल हो चुकी है। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम को बेचने की कगार पर खड़ा कर दिया है। आजतक देश में किसी भी अन्य नगर निकायों पर ऐसी नौबत नहीं आई कि उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़े। इसका सिर्फ एक कारण है भाजपा का भ्रष्टाचार और नाकामी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निगम का मूल काम साफ-सफाई का ध्यान रखना है लेकिन भाजपा कोई भी एक ऐसा वार्ड नहीं दिखा सकती जिसे मॉडल वार्ड कहा जा सके। भाजपा ने महामारी के दैरान अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों तक को वेतन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि निगम को दिल्ली के नागरिकों से टैक्स मिल रहा है, दिल्ली सरकार भी पैसे दे रही है उसके बावजूद निगम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और ऐसी हालत बन गई है कि एमसीडी को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ेगी।

दिल्ली में कोरोना के 576 नये मामले, 103 और मरीजों की मौत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में कोविड-19 के 576 नये मामले सामने आने के बाद शहर में संक्रमण की दर 0.78 प्रतिशत हो गई और बुधवार को 103 और मरीजों की बीमारी से मौत हो गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से कम दर्ज की गई है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रसार होने के बाद, दिल्ली में रोजाना के मामलों और मौतों में 19 अप्रैल के बाद से वृद्धि देखी गई थी। तीन मई को शहर में एक दिन में सर्वाधिक 448 मरीजों की मौत हुई थी।

हालांकि, पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के दैनिक मामलों और मरीजों की मौत की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 1,287 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में आज सामने आए कोविड-19 के 576 मामलों के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,27,439 हो गई है,जबकि मृतक संख्या बढ़कर 24,402 हो गई है। संक्रमण से मृत्यु दर 1।71 प्रतिशत है। इलाज करा रहे लोगों की संख्या 9,364 है जिनमें से 4,531 लोग घरों में पृथकवास में हैं।

पिछले साल केंद्र ने 15 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया था हमने 32 लाख लगाए : गोपाल राय

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हर साल केंद्र सरकार सभी राज्यों को वृक्षारोपण का लक्ष्य देती है। पिछली बार केंद्र सरकार ने दिल्ली को 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के वादे के अनुसार जो हमने दिल्ली के लोगों से चुनाव के समय 10 महत्वपूर्ण गारंटी दी थी, उसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए दो करोड़ पौधे लगाने का 5 साल में लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को देखते हुए हमने केंद्र सरकार के दिए हुए 15 लाख के लक्ष्य से दोगना लक्ष्य रखा था। हमने पिछले साल 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमें इस बात की खुशी है कि अपने लक्ष्य से ज्यादा 32 लाख पौधे पिछले एक साल में दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। इस बार केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए करीब 18 लाख वृक्षारोपण का दिया था। इस बार भी हम अरविंद केजरीवाल के गारंटी के अनुरूप उसको पूरा करने के लिए हमने इस दूसरे साल में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरूआत 5 जून से सांकेतिक रूप से करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति के कारण अभी अर्ध लॉकडाउन है। इसलिए 5 जून से इसकी हम सांकेतिक शुरूआत करेंगे और आगामी दिनों में बड़े स्तर पर इसका अभियान चलाया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर खासतौर से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने को लेकर के सब जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि इस कोरोना संकट के दौरान वही ब्रह्मास्त्र है, जिसका प्रतिरोधक तंत्र ठीक है, वह इस लड़ाई को लड़ कर जीत रहा है और जिसका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो रहा है, वो इस लड़ाई को हार जा रहा है। इसलिए वन विभाग की तरफ से दिल्ली के अंदर हमने पिछले साल प्रतिरोधक तंत्र बढ़ाने वाली जड़ी-बूटियों के पौधों को लगाने का अभियान शुरू किया था। जिसमें कढ़ी पत्ता, आंवला, बेहरा, जामुन, अमरूद, अर्जुन सहजन, बेल पत्ता, निबू, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय के पौधे लगाए गए। दिल्ली के अंदर जो सरकारी नर्सरी हैं, वहां से यह पौधे निःशुल्क दिए जाते हैं। 5 जून से इस साल भी हम इसकी शुरूआत करने जा रहे हैं। 5 जून को कोरोना से लड़ने वाली प्रतिरोधक जड़ी बूटियों का रोपण करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अलग-अलग एरिया में स्थित नर्सरी से यह पौधे लेकर अपने घर में लगाएं। इसके लिए बड़े स्थान की जरूरत नहीं है। कई सारी जड़ी बूटियां हैं, जिसको आप अपने घर पर गमलों में भी लगा सकते हैं। इसके सेवन से स्थाई तौर पर हम अपने प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ा सकते हैं। हमने पिछले साल जो अभियान चलाया था, उस दौरान 6.60 लाख पौधे लोग ले जाकर अपने घरों पर लगाया है। मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार और बढ़-चढ़कर इस अभियान को सफल बनाना है। जिससे कि हम इस कोरोना संकट में भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक तरीके से बढ़ा सकें।

मस्जिद में पानी लेने गई थी नाबालिग, मौलवी ने बनाया हवस का शिकार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद में पानी लेने गई 12 साल की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 48 साल के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर निवासी मौलवी को गाजियाबाद के लोनी जिले से सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौलवी को एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गाजियाबाद के लोनी जिले में रहता है और चार बच्चों का पिता है।

यह घटना रविवार शाम को घटित हुई। लड़की ने घर लौटकर अपने माता-पिता को आपबीती बताई। लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी पानी लाने मस्जिद गई थी, जहां मौलवी ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार लड़की की काउंसिलिंग की गई और इसके बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। पुलिस के अनुसार मस्जिद के आसपास पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि स्थानीय लोग विरोध के लिए वहां पहुंचे थे।

कोरोना की तीसरी लहर से पहले दिल्ली सरकार की तैयारी, मंत्री ने किया निर्माणाधीन शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण

नई दिल्ली । बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डाबड़ी स्थित दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। तीसरी लहर में बच्चों पर संकट गहराने के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्माण कार्य गति देने का आदेश दिया और कहा कि आगामी तीन माह के अंदर निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा किया जाए।

बता दें अस्पताल में फिलहाल 106 बेड है, जिनकी संख्या को बढ़ाकर 281 करने का लक्ष्य है। 54 करोड़ की इस परियोजना को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। नवंबर 2019 में विधानसभा चुनाव से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक विनय मिश्रा को अस्पताल के बगल में खाली पड़ी डीडीए की दो जमीनों को हस्तांरण कराने के लिए अधिकारियों से बात करने की बात कहीं है।

इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. ब्रजेश कुमार व अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डा. दीपमाला मौजूद रहीं। डा. ब्रजेश ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जच्चा-बच्चा सेवाएं काफी प्रभावित हुई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सहूलियत बढ़ेगी।

तीसरी लहर के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल हो रहा तैयार- तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए द्वारका सेक्टर-9 स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल का जल्द ही विस्तार कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर चल रहा है। पर तीसरी लहर से पूर्व यहां 1240 आक्सीजन बेड को शुरू करने की योजना है। जिसमें बच्चों के लिए भी 30 बेड का आइसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है।

ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि इंदिरा गांधी अस्पताल के पूर्ण रूप से शुरू होने के बाद तीसरी लहर के दौरान दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मामले कम होने के साथ ही अस्पताल का विस्तार कार्य धीमा हो गया है।

बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की कब्र को पक्का करने पर विवाद

नई दिल्ली । दिल्ली गेट स्थित जदीद कब्रिस्तान में बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पक्की कब्र बनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। यहां जगह की कमी को देखते हुए पहले से ही कब्र को पक्की करने की मनाही है। उसमें भी कोरोना संक्रमण के कारण अत्यधिक मौतों को देखते हुए तो इसपर पूरी तरह से रोक है, लेकिन उनकी कब्र को पक्की किया जा रहा है। जिसपर विवाद छिड़ गया है।

तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास सजा काट रहे शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण एक मई को निधन हो गया था। हालांकि, उनके घर वाले उनके शव को सीवान में पैतृक गांव में ही दफनाने के लिए ले जाना चाहते थे। पर इसकी मंजूरी नहीं मिली और उनके शव को दिल्ली गेट स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया।

अब उसी कब्र को पक्का करने का काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि जब इसे पक्का करने की शुरूआत हुई तो कब्रिस्तान की कमेटी ने उसे रूकवाने की भी कोशिश की। पुलिस भी बुला ली गई है। पर अब फिर से काम शुरू हो गया है। फिलहाल इसपर कमेटी का कोई सदस्य बोलने को तैयार नहीं है।

वहीं, मंसूरी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हसनैन अख्तर मंसूरी ने कहा कि आम लोगों के लिए अलग तथा पूर्व सांसद के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 में ही कब्रिस्तान कमेटी ने एक कानून बनाकर कब्र को पक्की करने पर रोक लगा दी थी। अब इस कब्र को जगह घेर कर ईंट से कैसे पक्की की जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए।

बता दें कि आरजेडी के पूर्व सांसद की शहाबुद्दीन की एक मई को कोरोना के कारण हो गई थी। इसके बाद उन्हें आइटीओ स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इस कब्रिस्तान में कब्र को पक्का करने की इजाजत नही है।

कोरोना संकट में भी नगर निगमों से भेदभाव कर रही है दिल्ली सरकारः आदेश गुप्ता

नई दिल्ली । भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार शुरू से नगर निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार का निगमों के साथ भेदभाव जारी है। पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार का बजट 37450 करोड़ रुपये से बढ़कर 69 हजार करोड़ रुपये हो गया। इसके विपरीत निगमों के बजट में कमी की जा रही है। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष निगम के लिए 6828 करोड़ रुपये का प्रविधान किया था। इस सिर्फ 6172 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस तरह से एक वर्ष में 656 करोड़ रुपये कर कर दिए गए।

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि तीसरे दिल्ली वित्त आयोग के अनुसार दिल्ली सरकार कुल कर संग्रह का 16.50 फीसद हिस्सा निगम को दे रही थी अब इसे घटाकर 12.50 फीसद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निगमों के 111 डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक व सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। सरकार इन्हें कोरोना योद्धा मानने से इन्कार कर रही है। इनके स्वजनों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। फंड की कमी से कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार को दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नगर निगमों को फंड देना होता है जिसकी उपेक्षा की जा रही है। निगमों के आठ में से छह अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए समर्पित किया गया। यदि निगमों द्वारा तैयार किए गए कोरोना केयर सेंटर को समय पर सरकार अनुमति देती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। दो सौ टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे जिसे दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए।

नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक नगर निगम से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं विधवाओं को पेंशन मिलती थी। लगभग दो लाख लोगों को इससे सहारा मिलता था। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही निगम द्वारा पेंशन वितरण पर रोक लगा दी। सरकार ने इन असहाय लोगों को कोई वैकल्पिक सहयता भी नहीं दी जिससे कोरोना काल में उनकी परेशानी बढ़ गई है। वहीं, भाजपा नेता इंटरनेट मीडिया पर निगमों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि अदालत से फटकार लगने के बावजूद दिल्ली सरकार निगमों को 13 हजार करोड़ रुपये बकाया नहीं दे रही है।

नई दिल्ली में कोविड-तालाबंदी के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा वितरित मुफ्त भोजन लेने के लिए कतार में बैठे जरूरतमंद लोग।

सुशील को स्कूटी देने वाली महिला खिलाड़ी से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अब क्राइम ब्रांच सुशील कुमार के खिलाफ मोबाइल फुटेज एवं गवाहों के बयान के आधार पर जांच करेगी। इसी को अपनी जांच का आधार बनाएगी। वहीं बुधवार को सुशील एवं अजय की पुलिस हिरासत अवधि खत्म हो रही है। जांच से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुशील एवं अजय को लेकर सोनीपत-हरिद्वार एवं पंजाब के अन्य ठिकानों पर पुलिस गई थी। लेकिन न तो मोबाइल मिला और न ही वारदात में प्रयुक्त डंडा एवं सुशील के कपड़े। यहां तक कि डीवीआर भी नहीं मिली जिसमें वारदात के दौरान के अहम सबूत छिपे हुए थे। पुलिस अधिकारी का कहना था कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। माना जा रहा है सुशील द्वारा प्रयुक्त सिम कार्ड को भी तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद पुलिस के पास गिरफ्तार आरोपी प्रिंस दलाल द्वारा बनाई गई वीडियो फुटेज और सोनू एवं अमित के बयान ही आधार हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ मौके पर मौजूद वाहन, मोबाइल फोन एवं लाइसेंसी बंदूक को अहम सबूत माना जा रहा है। जब स्पेशल सेल ने सुशील एवं अजय को गिरफ्तार किया था तब वो स्कूटी से मुंडका इलाके में घूम रहे थे। यह स्कूटी सुशील की महिला मित्र की थी जो राष्ट्रीय स्तर की हैंडबाल खिलाड़ी थी। अब पुलिस महिला खिलाड़ी को भी सुशील की मदद करने के आरोप में नोटिस देकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सबूत मिलने पर एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। अब पुलिस सुशील कुमार के खिलाफ साक्ष्य मिटाने की धारा भी दर्ज की गई है। दरअसल, वारदात में प्रयुक्त डंडा, मोबाइल फोन एवं अन्य सबूत नष्ट करने की जानकारी सामने आई है। इन्हें सुशीलके कहने पर नष्ट किया गया था। इसलिए साक्ष्य मिटाने की धारामें मुकदमा दर्ज किया गया है।

संपादकीय

मुसीबत में कितना काम आ रहा बीमा

मध्य प्रदेश की कारोबारी राजधानी इंदौर के जिलाधिकारी पिछले हफ्ते बीमा कंपनियों से नाराज हो गए। उन्होंने इन कंपनियों के नुमाइंदों की बैठक बुलाकर साफ चेतावनी दी कि जिस कंपनी ने भी इस वक्त क्लेम-सेटलमेंट में आनाकानी की, उसके खिलाफ वह एफआईआर दर्ज करा देंगे। खासकर कैशलेस पॉलिसी वाले लोगों को अप्रूवल आने में बहुत वक्त लग रहा था। जिलाधिकारी ने कहा कि इस काम में दो घंटे से ज्यादा वक्त लगा, तब भी कार्रवाई होगी और कंपनियों के हेड ऑफिस में बैठे बड़े अफसरों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। यह मामला तो इंदौर का है, लेकिन देश के अनगिनत शहरों और कस्बों में भी लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। पहले तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। रो-पीटकर उसका इंतजाम हो जाए, तो बीमा कंपनी से अप्रूवल आने में घंटों का इंतजार। ऐसे में, लगता है कि कैशलेस हेल्थ पॉलिसी एक बेकार कागज का टुकड़ा है। यह हाल तब है, जब पिछले साल कोरोना फैलने के कुछ ही समय बाद इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सभी स्वास्थ्य बीमाओं में कोरोना को शामिल करने का आदेश दिया था। इससे भी बड़ी दिक्कत उन लोगों की है, जिनके परिवार में किसी की कोरोना से मौत हो गई है। खासकर, बेड न मिलने या समय पर न चेतने की वजह से यदि मौत अस्पताल के बजाय घर में हुई हो। ऐसे अनेक मामलों में शिकायत यह मिल रही है कि न तो सरकार उसे कोरोना का मामला मानने को तैयार है, न बीमा कंपनियां क्लेम देने को। हालांकि, इसी चक्कर में स्वास्थ्य बीमा व जीवन बीमा, दोनों के प्रीमियम में तेज उछाल आ चुका है। पिछले वर्ष अगस्त में खबर आई थी कि देश भर में कोरोना से 50,000 मौतों के बावजूद बीमा कंपनियों के पास सिर्फ एक हजार ऐसे दावे आए थे, और उनमें से छह सौ का भुगतान किया गया था। हालांकि, तब तक देश में कोरोना के 26 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। उधर स्वास्थ्य बीमा के करीब एक लाख क्लेम सिर्फ अगस्त में जमा किए गए। पर कंपनियों ने तभी बता दिया था कि इनमें से एक चौथाई दावे तो पहली नजर में ही खारिज होने हैं, क्योंकि वे मरीज अस्पताल नहीं गए थे।

यह हाल तब था, जब पिछले साल अप्रैल में ही यह तय हो चुका था कि बीमा कंपनियां कोरोना से होने वाली मौत का कोई दावा खारिज नहीं करेंगी। लाइफ इंश्योरेंस कौंसिल ने यह फैसला किया था। इसकी वजह यह बताई गई कि भारत में बहुत कम लोग बीमा कराते हैं। इरडा के आंकड़ों के हिसाब से 2019 के अंत तक भारत में 25.7 फीसदी लोगों के पास ही बीमा थी। लेकिन यह अधूरी तस्वीर है। दुनिया के बहुत बड़े री-इंश्योरर 'स्विस आरई सिग्मा' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 3.76 प्रतिशत है, जबकि दुनिया का औसत है 7.23 फीसदी। मतलब यह कि जितना इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका सिर्फ पौने चार फीसदी के आसपास ही है। 25 फीसदी लोगों के पास पॉलिसी होने के बाद भी ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि जिन लोगों ने बीमा ले रखा है, उनमें से भी ज्यादातर ने अपनी कमाई और जरूरतों के मुकाबले काफी कम बीमा कवर लिया हुआ है। यही वजह है कि दावे इतने कम आए। हालांकि, उसके बाद दावे काफी बढ़े हैं और सख्ती भी। मार्च तक ही भारत की जीवन बीमा कंपनियां कोरोना से हुई मौतों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान कर चुकी थीं। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पास ऐसे 9,30,000 दावे आए थे और 14,000 करोड़ रुपये की मांग। हालांकि, उन्होंने सिर्फ 7.96 लाख क्लेम मंजूर किए और करीब 7,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया। लेकिन इसका नतीजा यह होना है कि अब अगले साल, यानी अप्रैल 2022 से जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम काफी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां तो पिछले साल ही अपने प्रीमियम करीब 20 फीसदी तक बढ़ा चुकी हैं। इरडा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना के कारण स्वास्थ्य बीमा करने वाली देश की 21 में से नौ निजी कंपनियां और चार में से तीन सरकारी कंपनियां घाटे में चली गई हैं। जीवन बीमा कंपनियां बची हुई थीं, पर कोरोना की दूसरी लहर का असर उन पर भी ऐसा ही दिख सकता है। अब तीसरी लहर की बात होने लगी है। वह हुआ, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा और इनमें से कितनी कंपनियां बाजार में बचेंगी, कहना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि आप कितने का भी बीमा करा लें, यदि वक्त पर अस्पताल न मिला, तो वह पॉलिसी किस काम की? यही सवाल भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना पर भी है? और अपनी जनता के इलाज को बीमा के भरोसे छोड़ देने वाले समाजों का हाल देखना है, तो माइकल मूर की शानदार फिल्म सिको देखनी चाहिए। इसमें दिखता है कि निजी अस्पताल, फार्मा और बीमा कंपनियों के भरोसे टिका अमेरिकी स्वास्थ्य ढांचा मरीज को कैसे बेसहारा छोड़ देता है। इसके मुकाबले कनाडा व इंग्लैंड में सरकारी अस्पतालों के भरोसे चलने वाले सिस्टम कितने ज्यादा कारगर हैं, इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है। मैं खुद उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में पैदा हुआ, जो अब उत्तराखंड है। दोनों राज्यों के अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में पला-बढ़ा। इन सभी जगहों पर तब किसी भी बीमारी के लिए आसपास के डॉक्टर या खुद को डॉक्टर कहने वाले कंपाउंडर के बाद पहला और आखिरी ठिकाना होता था, सरकारी अस्पताल। तब निजी अस्पताल शायद होते नहीं थे। नर्सिंग होम जरूर खुलने लगे थे, लेकिन उन्हें शक की निगाहों से ही देखा जाता था। लेकिन पिछले चार दशकों में वह सब कहां चला गया, समझ नहीं आता। आजादी के बाद जो ढांचा खड़ा हुआ था, उसे और मजबूत करने की जगह ध्वस्त करने की कीमत हम आज चुका रहे हैं। लेकिन अब भी सबक सीख लें, तो आगे काफी कुछ बच सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा की जगह किसी बीमा कंपनी की कोई स्किम नहीं ले सकती। गांव-कस्बों में छोटे अस्पताल और जिलों व मंडलों में उससे बेहतर अस्पताल, दो-चार जिलों के बीच एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल। यह सब सरकार के हाथ में रहे और काम भी करे, तभी मुसीबत के वक्त लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी। अन्यथा, घूमते रहेंगे हाथों में हेल्थ कार्ड लेकर, जरूरत के वक्त न अस्पताल दिखेंगे,और न जरूरी दवाएं।

प्रवीण कुमार सिंह

लोगों तक पहुंचने से पहले बर्बाद हो रहा टीका, तय हो जवाबदेही

सवाल केवल दवा की कुछ खुराक के खराब होने का नहीं है, यह लोगों के जीवन से जुड़ा मसला है। कोरोना से बचाव के लिए देशभर में टीकाकरण के दायरे में सभी वयस्कों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन उपलब्धता के अभाव में समूची आबादी के टीकाकरण में कई माह का समय लग सकता है। ऐसे में उपलब्ध वैक्सीन की प्रत्येक डोज का इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। कई कारणों से वैक्सीन की काफी डोज की बर्बादी हो रही है। ऐसे में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। इसकी बर्बादी के लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ देशभर में टीकाकरण की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। विज्ञानियों ने कयास लगाया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने अवसान के समीप है और तीसरी लहर की शुरुआत होने वाली है, जिसमें बच्चों के अत्यधिक संक्रमित होने की चिंता जताई गई है। इसी आशंका से सरकार टीकाकरण को गति देने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि एक मई से सरकार ने 18 की उम्र को पार कर चुके लोगों के लिए भी टीकाकरण का रास्ता खोल दिया है। देश में टीके की कमी के बीच पिछले दिनों केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अगस्त से दिसंबर के बीच पांच महीनों में देश में दो अरब से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी, जो पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन उससे पहले टीके की बढ़ती बर्बादी को कम करने पर काम करना होगा।

बहरहाल, देश में अब तक लगभग 18 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। जहां अभी भी देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण करना बड़ी चुनौती है, वहीं लगातार टीके की बर्बादी सरकार के लिए चिंता का कारण है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकों की बर्बादी रोकने के लिए केरल की तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी कम करना सबसे अहम है। यह पहला ऐसा अभियान है, जिसके तहत समूची वयस्क आबादी का टीकाकरण होना है। देश में कोविड टीके की औसतन 6.5 फीसद खुराक बर्बाद हो रही है। पिछले दिनों हरियाणा में 2.29 लाख लोगों को लगाई जा सकने वाली वैक्सीन बेकार चली गई। दुख की बात है कि वैक्सीन बर्बादी के मामले में तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पंजाब, मणिपुर और तेलंगाना सबसे आगे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि तमिलनाडु वैक्सीन बर्बादी की सूची में शीर्ष पर है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 12.1 फीसद वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, जहां अब तक 9.7 प्रतिशत डोज की बर्बादी हो चुकी है। पंजाब में 8.1 प्रतिशत, मणिपुर में आठ प्रतिशत और तेलंगाना में 7.5 प्रतिशत, जबकि राजस्थान में 5.5 प्रतिशत और बिहार में 4.9 प्रतिशत और मेघालय में 4.2 फीसद कोविड वैक्सीन बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं सबसे कम वैक्सीन बर्बाद करने वालों में अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल और मिजोरम शामिल हैं। अन्य राज्यों को इन राज्यों से सीख लेनी चाहिए।

सवाल उठता है कि आखिर ये वैक्सीन बर्बाद क्यों हो रही है? एक तरफ निरंतर वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, तो दूसरी ओर इसकी बर्बादी।

आखिर क्या कारण है? दरअसल वैक्सीन की एक शीशी में 10 से अधिक डोज आती है और अगर शीशी एक बार खुल जाती है, तो सिर्फ चार घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वैक्सीन खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टीके के भंडारण के लिए निर्देश जारी किया था कि टीकों को दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ही रखना जरूरी होगा। इसका सही अनुपालन न होना भी टीका बर्बादी का कारण बन रहा है।

राज्यों में टीकाकरण की ताजा समीक्षा रिपोर्ट में पता चला है कि देश में कोरोना टीकाकरण के दौरान विभिन्न राज्यों में टीके की 58 लाख से भी अधिक खुराकें बर्बाद हुई हैं। केंद्र सरकार ने प्रति खुराक 150 रुपये की दर से इन्हें खरीदा था। इस हिसाब से टीकाकरण के लगभग 90 दिनों के भीतर ही सरकार को 87 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। गौरतलब है कि सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में ही अब तक दी गई 1.06 करोड़ खुराकों में से 95 लाख का इस्तेमाल हुआ, जबकि पांच लाख से अधिक खुराकें नष्ट हो गईं। इस वजह से करीब साढ़े सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसलिए जरूरी है कि टीके की बर्बादी पर राज्यों की जवाबदेही तय की जाए। यह टीका एक संजीवनी है, जो लोगों के प्राण की रक्षार्थ उपयोग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण टीके की बर्बादी जारी है, जो अधिक चिंता का विषय बनता जा रहा है। टीके की बर्बादी रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकरणों की है। अगर स्थानीय प्रबंधन मजबूत बनाया जाए तो इसमें कमी अवश्य लाई जा सकती है। छोटे टीकाकरण केंद्रों को भी मजबूत करने की जरूरत है। टीके की बर्बादी का एक प्रमुख कारण लोगों द्वारा समय लेने के बावजूद टीका लगवाने न पहुंचना है। विशेषज्ञों ने वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए एक तरीका सुझाया है, जिसमें टीकाकरण केंद्रों के पास एक किमी के दायरे में रह रहे लोगों का डाटा तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे फोन कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए बुला सकें। खुराकों को फेंकने से बेहतर गैर-पात्र लोगों को वैक्सीन लगाना है। इससे बर्बाद होने वाली खुराकों को बचाया जा सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि दिन के अंत में, शीशी में कुछ खुराकें बाकी हैं तो उन्हें जरूरतमंद लोगों को दिया जाए। भले ही ऐसे व्यक्ति टीकाकरण के लिए निर्धारित श्रेणी में नहीं आते हों। वास्तव में इस उपाय को राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये टीके अमूल्य हैं। टीके की बर्बादी कम होने से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सकेगा। सभी राज्यों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में जाने अनजाने किसी भी तरह की लापरवाही न हो। सवाल केवल दवा की कुछ खुराक के खराब होने का नहीं है, यह लोगों के जीवन से जुड़ा मसला है।

कोरोना से बचाव के लिए देशभर में टीकाकरण के दायरे में सभी वयस्कों को शामिल कर लिया गया है, लेकिन उपलब्धता के अभाव में समूची आबादी के टीकाकरण में कई माह का समय लग सकता है। ऐसे में उपलब्ध वैक्सीन की प्रत्येक डोज का इस्तेमाल सुनिश्चित होना चाहिए। कई कारणों से वैक्सीन की काफी डोज की बर्बादी हो रही है। ऐसे में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। इसकी बर्बादी के लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार की दूर-दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आती

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के 2 मई को आए नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस और उसका मौजूदा नेतृत्व चुनावी राजनीति में जीत हासिल करने लायक नहीं है। खासकर केरल में उसकी हार ने उसके विरोधियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि इस राज्य के मतदाता पिछले 40 साल से हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वाम गठबंधन की सरकार को फिर से चुनकर यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जाहिर है कि देश को आजादी दिलाने और उसे वैज्ञानिक सोच के साथ विकास के पथ पर ले जाने का दावा करने वाली कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। हालांकि कांग्रेस इससे पहले 1980 और 2004 में केंद्र की सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन अब न तो उसके पास कोई दृष्टि और न ही कोई नेता। कांग्रेस की इस दुर्गति को पार्टी के प्रवक्ता रहे संजय झा ने अपनी ताजा पुस्तक ब्रद्ध ग्रेट अनरैवेलिंगः इंडिया आफ्टर 2014ब्क में बेहतरीन ढंग से पेश किया है।

पिछले साल जुलाई में पार्टी से निलंबित किए जाने से पूर्व संजय झा कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य को लेकर अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण पार्टी प्रवक्ता पद से हटाए जा चुके थे। पिछले साल जून में एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख के कारण उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया गया था। प्रस्तुत पुस्तक एक तरह से उनके उसी लेख का विस्तार है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के इस दावे को खारिज किया था कि पार्टी के अंदर विचारों के खुले आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध है। इसके बाद कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं (जी-23) की चिट्ठी ने कांग्रेस नेतृत्व पर

सवालों की बौछार कर दी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नींद नहीं खुली और उसके नतीजे सबके सामने हैं। कांग्रेस की कार्यशैली और उसके नेतृत्व पर प्रश्न खड़े करने वाले संजय झा ने पिछले साल जब जी-23 की चिट्ठी को लेकर पहली बार ट्वीट किया था तो पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें भाजपा का एजेंट तक कह दिया था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे अब भी कांग्रेसी ही है और पार्टी के भविष्य को लेकर वाकई में चिंतित हैं। सोनिया गांधी के आमंत्रण पर 2004 में पार्टी से जुड़ने वाले संजय झा की इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस के पराभव के कारणों के विश्लेषण में काफी ईमानदारी बरती है। हालांकि वे राहुल गांधी को अब भी लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं, लेकिन उनकी कमियां बताने में भी वे पीछे नहीं रहे हैं। शाहबानो प्रकरण के बहाने उन्होंने राजीव गांधी की भी जमकर आलोचना की है। पार्टी को पटरी पर लाने के लिए हालांकि उनके सुझाव नए नहीं है। उनकी राय है कि किसी गैर-गांधी को पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहिए। कोई ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी का मुकाबला कर सके। उन्होंने इसके लिए कुछ नेताओं के नाम भी सुझाए हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि पार्टी का एक वर्ग नहीं चाहता है कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी गैर-गांधी के पास जाए क्योंकि ऐसा होने की सूरत में उनकी और उनके बेटे-बेटियों की राजनीति खत्म हो जाएगी। संजय झा की नजर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जरिए पार्टी पर कुंडली मारे बैठे इन नेताओं के रहते तो पार्टी का भविष्य अंधकारमय ही लगता है।

कांग्रेस को लेकर चिंता जताने के अलावा इस पुस्तक का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार और उसकी विचारधारा एवं नीतियों पर केंद्रित है। जैसी कि किसी कांग्रेसी से उम्मीद थी, इस लेखक को भी लगता है कि मोदी सरकार के कारण भारत की उदार, सेक्युलर और वैज्ञानिक अवधारणा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और इस वजह से इस महान देश की छवि को गहरा धक्का लगा है। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है और उसकी विदेश नीति तदर्थता का शिकार हो गई है। वे यह भी मानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारत को फिर से वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकती है। पाठकों का संजय झा के निष्कर्षों से मतभेद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि वे इस पुस्तक में एक सच्चे कांग्रेसी की भूमिका में नजर आए हैं।

देश के सबसे पुराने प्रबंधन संस्थानों में शामिल जमशेदपुर के जेवियर स्कूल आफ मैनेजमेंट के ग्रेजुएट संजय झा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पदों पर रहने के बाद राजनीति की दुनिया में आए हैं। इसलिए कांग्रेस को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ट्विटर और दूसरे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों से बाहर निकल कर सड़क पर उतरे और जनता के संघर्षों में शामिल हो। इसके बिना कांग्रेस का पुनरुद्धार की दूर-दूर तक संभावना नजर नहीं आती है।

विदेश में बसने की होड़

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई ऐसे लोगों ने भी अपने करीबियों को गंवाया है, जिनके पास इलाज के लिए पैसे की कमी नहीं थी। कइयों को जब अपने परिजनों या करीबियों के लिए अस्पताल में बेड की जरूरत थी, तब उन्हें बेड नहीं मिला। ऑक्सिजन सिलिंडर, रेमडेसेवियर या अन्य दवाओं को लेकर भी उन्हें उतनी ही परेशानी उठानी पड़ी। अप्रैल और मई में इन वजहों से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इससे लोग आहत हैं और उनमें से कई अब देश छोड़ रहे हैं या उसकी योजना बना रहे हैं। वीजा और इमिग्रेशन सर्विस देने वाली कंपनियां के पास पिछले दो महीनों में विदेश में बसने को लेकर पूछताछ करने वालों की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, कंपनियों को लगता है कि दूसरी लहर में बीमार हुए और लोग ठीक होंगे तो विदेश में बसने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

ऐसा नहीं है कि सामान्य वक्त में भारतीय विदेश में बसना नहीं चाहते। कोरोना महामारी के दस्तक देने से पहले भी कुछ हजार लोग हर साल देश छोड़कर जा रहे थे। उस वक्त वीजा और इमिग्रेशन सर्विस कंपनियों के पास 90 फीसदी ऐसे लोग आते थे, जो बिजनेस बढ़ाने, आसान टैक्स नीतियों और कारोबार में आसानी की वजह से दूसरे देशों में बसना चाहते थे। ये सब अमीर तबके के लोग होते थे। इस बार का मामला अलग है। अब मध्यवर्गीय लोग भी विदेश जाकर बसना चाहते हैं। उनकी प्रायॉरिटी तय है। वे ऐसे देशों में बसना चाहते हैं, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में।

देश में ऐसे माता-पिता की भी बड़ी संख्या है, जिनके बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में इनमें से कइयों के पैरंट्स संक्रमित हुए। उनके इलाज में परेशानी हुई। इसलिए अब ये बच्चे अपने माता-पिता को अपने पास बुलाने को बेचैन हैं। पिछले साल सितंबर में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में जितने रईस हैं, उनमें से दो फीसदी यानी 7,000 लोग 2019 में विदेश जा बसे। इस साल के अंत तक यह संख्या और बढ़ेगी और इसमें मध्यवर्गीय लोगों का भी अच्छा-खासा हिस्सा होगा। सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझना होगा। उसे इस 'ब्रेन ड्रेन' को रोकना होगा। समझना होगा कि यह वर्ग न सिर्फ टैक्स के रूप में अच्छा-खासा योगदान देता है बल्कि देश की आर्थिक तरक्की में भी इन कुशल पेशेवरों की बड़ी भूमिका है। आज यह वर्ग देश में अपर्याप्त हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से नाराज है। सरकार को इसमें निवेश बढ़ाना चाहिए, जिसकी सलाह यूं भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स लंबे समय से देते आए हैं। इससे न सिर्फ अगली मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि देश से ब्रेन ड्रेन भी रुकेगा।अब मध्यवर्गीय लोग भी विदेश जाकर बसना चाहते हैं। उनकी प्रायॉरिटी तय है। वे ऐसे देशों में बसना चाहते हैं, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में।

कोविड की दूसरी लहर के बीच गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास

आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, होमगार्ड और यहां तक कि स्कूल के शिक्षकों को पीएचसी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कोविड केंद्रों में फंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में तैनात किया जा सकता है। मोबाइल वैन के माध्यम से बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को परीक्षण, आइसोलेशन, दवा और टीकाकरण के अभियान में शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार उद्योगपतियों से उनके सीएसआर फंड के तहत वित्तीय मदद ले सकती है। इन तमाम एकीकृत प्रयासों से ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करते हुए कोरोना के कहर को नियंत्रित कर सकती हैं।

कोविड की दूसरी लहर ने देश में सुनामी की तरह दस्तक देते हुए हमें जैसे सुसावस्था में ही धर लिया। विश्वभर से संकेत मिल रहे थे कि कोरोना एक आक्रांता के रूप में वापस आ रहा है, परंतु ये अनुमान किसी को न था कि हम भी इससे इतनी बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। अप्रैल के आखिरी काल से देश में कोरोना के प्रतिदिन साढ़े तीन से चार लाख के बीच मामले आ रहे हैं, वह भी तब जब हमारी कोरोना परीक्षण की व्यवस्था ज्यादा विस्तृत नहीं है। उल्लेखनीय है कि कृषि प्रधान पंजाब और हरियाणा की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन राज्यों में भी कोरोना के मामलों में निरंतर वृद्धि हुई है। इस संबंध में जारी किए जा रहे तमाम आंकड़ों को देखें तो कोविड के दैनिक बुलेटिन में ग्रामीण और शहरी मामलों को अलग-अलग करके नहीं दर्शाया जा रहा। यह तब हो रहा है जब कोविड मामलों के लिए राज्य सरकारें अस्पतालों और परीक्षण प्रयोगशालाओं पर निर्भर हैं, जो मामलों का संकलन करके इसकी रिपोर्ट नोडल एजेंसियों से साझा करती हैं और एजेंसी इसे आगे सरकार को देती है। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अधिकांश राज्यों को आभास ही नहीं हुआ कि उनके ग्रामीण इलाकों में यह संकट बढ़ रहा है। प्रचार और राजनीतिक रूप से हटकर देखें तो कोरोना वायरस ने हमें लिटमस टेस्ट में धकेल दिया है जिसमें हमें किसी भी कीमत पर पास होना होगा। हम परीक्षण और उपचार के लिए अपने लोगों को पीड़ित होते, मरते हुए नहीं देख सकते। केंद्र और

राज्य सरकारों के लिए यह सही समय है कि वे अपना ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रबंधन और उसे काबू करने पर केंद्रित करें। अगर ग्रामीण भारत कोरोना के मकड़जाल में फंस गया तो यह हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी विनाशकारी होगा।

यदि राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी परीक्षण सुविधाओं का विस्तार कर दें, तो उनसे कोरोना संक्रमण के मामलों के जो आंकड़े सामने आएंगे वो कई गुना अधिक और काफी चिंताजनक हो सकते हैं। मौजूदा संसाधनों का यदि ठीक से उपयोग किया जाता है, तो भी ये ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संकट को कम करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में 23 जुलाई, 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को लिखित जवाब में सूचित किया था कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25,743 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) हैं, जबकि जरूरत 29,337 केंद्रों की है। ऐसे में आज इन पीएचसी को कोविड महामारी के चलते ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत अपग्रेड करने की जरूरत है। दरअसल महामारी के समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र ही वो जगह हैं जहां आकर ग्रामीण लोग सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं।

एक पीएचसी का अपग्रेड होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि चिंता और बेचैनी में हड़बड़ा कर जिला या सब-डिवीजन स्तर के अस्पतालों की ओर भाग रहे लोगों को रोका जा सके। वैसे भी शहरों के अस्पताल पहले ही क्षमता से अधिक भार से दबे हुए हैं। गांव में जांच के लिए शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। इन केंद्रों के प्रयासों को आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी जोड़ा जा सकता है। इनका उपयोग अन्य बीमारियों से पीड़ित उन लोगों की पहचान करने में भी किया जा सकता है जो महामारी के दौरान और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। शहरों की तरह वे ग्रामीण क्षेत्रों में एकांतवास और थमिक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जागरूकता कैंप लगा सकते हैं।

प्राय- देखा गया है कि आज भी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिना शारीरिक तापमान की जांच किए और बिना हाथ सेनिटाइज किए सुबह और शाम की प्रार्थना के लिए लोग धर्मिक स्थलों में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ राज्यों के ग्रामीण इलाकों में तो अब भी ताश खेलते लोगों के झुंड देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह बताने की सख्त जरूरत है कि आपसी दूरी बनाने और मास्क पहनने से कोविड के विरुद्ध जारी हमारी जंग सफल हो सकती है। तापमान को मापना, शारीरिक दूरी बरकरार रखना, मास्क का उपयोग करना और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखने जैसे सरल उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को बल मिलेगा।

हमारे अधिकांश जिला अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। इसमें भी हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। मात्र एक इच्छाशक्ति की जरूरत है जो कोरोना संकट में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट की जरूरत है। इसके लिए पीएचसी और मोबाइल परीक्षण वैन कारगर सिद्ध होंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को तुरंत अलग करने और दवा देने में मददगार सिद्ध होगा। स्कूलों परिसरों को आक्सीजन की सुविधा वाले कोविड आइसोलेशन केंद्रों में परिवर्तित किया जा सकता है।

आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, होमगार्ड और यहां तक कि स्कूल के शिक्षकों को पीएचसी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कोविड केंद्रों में फंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में तैनात किया जा सकता है। मोबाइल वैन के माध्यम से बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को परीक्षण, आइसोलेशन, दवा और टीकाकरण के अभियान में शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार उद्योगपतियों से उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड के तहत वित्तीय मदद ले सकती है। इन तमाम एकीकृत प्रयासों से ही हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करते हुए कोरोना के कहर को नियंत्रित कर सकती हैं। साथ ही, संभावित तीसरी लहर से बचाव की तैयारी भी कर सकते हैं।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

यूजी व पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक, बाकी छात्र होंगे प्रमोट

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में स्नातकव स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 अगस्त, 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी और इसके बाद 31 अगस्त तक परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति का फार्मूला तय करने के बाद विश्वविद्यालयों व कालेजों को यह निर्देश जल्द भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ऐसे विश्वविद्यालय जहां प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं, वहां विद्यार्थियों के द्वितीय वर्ष के अंक प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर निर्धारित कर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नति दे दी जाएगी। विश्वविद्यालय विवि जहां प्रथम वर्ष की परीक्षाएं वर्ष 2020 में नहीं हो पाईं थीं और विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया था, वहां छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा देकर ही तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाएंगे। इसी तरह वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू करने वाले संस्थानों में पीजी के छात्रों को भी प्रोन्नति दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक राय सहित तीन कुलपतियों की बनाई गई उच्चस्तरीय कमेटी के सुझाव के अनुसार यूजी व पीजी में सेमेस्टर प्रणाली के तहत पढ़ाई करा रहे विश्वविद्यालय व कॉलेजों में जहां प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे संस्थान जहां तृतीय व विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां इनके अंकों के आधार पर चतुर्थ व सम सेमेस्टर में प्रोन्नति दी जाएगी। फिलहाल यूजी व पीजी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के साथ ऐसे संस्थान जहां यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जाएंगी, वहां प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय सवाल ही पूछे जाएंगे। एक विषय के सभी प्रश्नपत्रों को सम्मिलित करते हुए एक प्रश्नपत्र ही तैयार किया जाएगा। यानी छात्र को एक विषय में सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति का फार्मूला तय करने के बाद विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को यह निर्देश जल्द भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। प्रायोगिक परीक्षा के अंक लिखित के आधार पर तय होंगे - विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होंगी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रैक्टिकल के अंक भी तय किए जाएंगे। मौखिक परीक्षाएं आनलाइन आयोजित की जाएंगी।

बिहार में लड़कियों को सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, अब मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में मिलेगा 33फीसद आरक्षण

पटना । यह बिहार की लड़कियों के लिए बड़ी खबर है। अब राज्य की 33 फीसद मेडिकल व इंजीनियरिंग सीटों पर उन्हें आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इसकी घोषणा की। बैठक में बिहार में मेडिकल व इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयकों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में अभियंत्रण विश्वविद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रस्तावित विधेयक प्रस्तुत किए। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने 'द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट- 2021' और पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, जुरिडिक्शन एवं अदर प्रॉविजन' के विषय में जानकारी दी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 'बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, जुरिडिक्शन एवं अदर प्रॉविजन' की बाबत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंत्रण और चिकित्सा विश्वविद्यालयों की सथापना के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन तो सुधरेगा ही, साथ ही अच्छी पढ़ाई भी होगी।

लड़कियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल में 33 फीसद आरक्षण- बैठक में खास बात इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक तिहाई सीटों को लड़कियों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लड़कियों में उच्च और तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। व इस ओर प्रेरित होंगी। बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इन दिनों सरकार ने कई मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए बिहार के विद्यार्थियों को राज्य के बाहर नहीं जाना पड़े।

चनपटिया में दिनदहाड़े चूड़ा मिल मालिक के भांजे से 5.50 लाख की लूट

पश्चिम चंपारण । बेतिया - चनपटिया मुख्य पथ पर बुधवार की शाम खरदेउर महना के समीप सशस्त्र बदमाशों ने बेतिया के चूड़ा मिल मालिक के भांजे चंदन कुमार से हथियार के बल पर 5.50 लाख लूट लिया है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश चनपटिया की ओर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। चनपटिया के श्याम सिनेमा हॉल के समीप के रहने वाले चंदन कुमार के मामा का गुलाबबाग बेतिया में चूड़ा मिल है। चंदन मिल के काम में सहयोग करता है। बताया जाता है कि चंदन अपने साथी चितरंजन शर्मा के साथ हथुवा बाजार से रुपये लेकर बाइक से घर लौट रहा था। रुपये को शर्ट के नीचे छुपा कर रखा था। महना के समीप काले रंग के पल्सर बाइक पर तीन बदमाश रास्ते में खड़े थे। बदमाशों ने चंदन कुमार को रोक लिया। इसी बीच दूसरे बाइक पर तीन बदमाश वहां पहुंच गए। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर चंदन कुमार से रुपये छीन लिया। इस दौरान उसके शर्ट को भी फाड़ डाले। बदमाशा चनपटिया की ओर फरार हो गए। चंदन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चनपटिया थानाध्यक्ष मनीष कुमार, बलथर थानाध्यक्ष राजेश झा, गोपालपुर थानाध्यक्ष राजरूप राय, कुमारबाग ओपी प्रभारी राणा प्रसाद, एसडीपी-एसटी थानाध्यक्ष सुजीत दास मौके पर पहुंच गए है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

मालेरकोटला बना पंजाब का 23वां जिला, कैबिनेट ने दी मंजूरी

चंडीगढ़ । मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को मलेरकोटला को जिला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 14 मई को ईद के मौके पर की थी। पंजाब की कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में कई निर्णय लिए गए और कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंजाब सरकार द्वारा गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कंपनी बनाने को भी मंजूरी दे दी। गांव में शुद्ध पेयजल उपलब करवाने के लिए पंजाब सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली कंपनी बनाई है। कंपनी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह कंपनी पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ मेंटिनेंस का काम भी करेगी। इस कंपनी को पंजाब रूरल वाटर यूटिलिटी कंपनी नाम दिया गया है। यह कंपनी जलापूर्ति व सेनिटेशन विभाग के अधीन होगी। पंजाब कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। कैबिनेट ने ऐतिहासिक कस्बे मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाए जाने को औपचारिक मंजूरी दी। मंत्रिमंडल द्वारा सब तहसील अमरगढ़ को सब-डिवीजन/तहसील बनाने को भी मंजूरी दी गई। पहले यह मलेरकोटला सबडिवीजन के तहत था। मलेरकोटला जिले में तीन सब-डिवीजन मलेरकोटला, अहमदगढ़ व अमरगढ़ शामिल होंगे। इसके अलावा जिले में 192 गांव, 62 पटवार सर्कल और 6 कानूनगो सर्कल भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 14 मई को ईद-उल-फितर के मौके पर मलेरकोटला को जिला बनाने का ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करने का एलान किया था। कैबिनेट की बैठक में कहा इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए लिए गए इस फैसले का मकसद मलेरकोटला के शहरी विकास को यकीनी बनाना, इस ऐतिहासिक शहर के समृद्ध विरसे को कायम रखना और इस क्षेत्र के समूचे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को 12 विभागों पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, सामाजिक न्याय और अल्प संख्यक, कृषि और किसान विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन, उद्योग एवं वाणिज्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अलावा वित्त के दफ्तरों के लिए नए पद सृजन करने जाने को मंजूरी देने के लिए अधिकार सौंप दिए।

कोरोना कर्फ्यू से छूट के दौरान लापरवाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज, बोले- सभी का सहयोग जरूरी

लखनऊ । कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बहुत अच्छी हो रही है। सतत प्रयासों से अब पूरे प्रदेश में एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 30 हजार से भी कम हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संतोष जताया है। हालांकि उन्होंने कोरोना कर्फ्यू में राहत के बाद कई जिलों में लोगों के मास्क न लगाने, बाजारों में अनावश्यक भीड़, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने जैसी मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि कोरोना कर्फ्यू से छूट का आशय लापरवाही की छूट होना नहीं है। यह स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं है।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 का बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। पुलिस प्रशासन को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक भी करें, साथ-फुट पेट्रोलिंग, चेकिंग और आवश्यकतानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। रात्रिकालीन बंदी को प्रभावी बनाने के लिए शाम छह बजे से ही पुलिस व स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाएं। पब्लिक एड्रेस सिस्टक का उपयोग करें। कहीं भी भीड़ की स्थिति न बने।

18+ को कोविड सुरक्षा कवर देने में यूपी प्रथम = मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब तक 1,51,81,813 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35,05,573 लोग वैक्सीन के दोनों डोज दी जा चुका है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक वैक्सीन के कुल 1 करोड़ 86 लाख 87 हजार 386 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। एक जून से प्रारंभ सभी 75 जिलों में 18+ आयु के टीकाकरण अभियान में लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। इस महाभियान के पहले दिन एक जून को साढ़े 5 हजार सेंटरों पर 3,42,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन का सुरक्षा-कवर प्रॉप्त किया। इस क्रम को और बेहतर किया जाए।

जनरल ओपीडी शुरू करने के निर्देश = मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन निःशुल्क है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई है। वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया की समुचित व्यवस्था हो। लोगों को कम से कम समय तक प्रतीक्षारत रहना पड़े। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस महाभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश में स्थिति तेजी से बेहतर हो रही है। हमारे 64 जिलों में 600 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सीमित संख्या के साथ जनरल ओपीडी का प्रारंभ किया जाए। ओपीडी में आने के लिए मरीज का समय पूर्व निर्धारित हो। अपॉइंटमेंट सिस्टम अनावश्यक भीड़ को रोकने में कारगर होगा। इमरजेंसी सेवाएं चौबीसों घंटे जारी रखी जाएं। अब तीन से चार दिन का आक्सीजन बैकअप = मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि आक्सीजन की मांग, आपूर्ति और खर्च में संतुलन बनाने के लिए कराए जा रहे आक्सीजन ऑडिट के अछे परिणाम मिले हैं। सतत नियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि आज अधिकांश मेडिकल कॉलेजों और रिफिलर्स के पास में तीन से चार दिन का आक्सीजन बैकअप हो गया है। बीते 24 घंटों में 454.7 मीट्रिक टन आक्सीजन का वितरण किया गया है। औद्योगिक इकाइयों को आक्सीजन के उपयोग की अनुमति दी जा चुकी है। इन गतिविधियों को सुचारु रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी के क्रम में मानव संसाधन का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण जारी है। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ आदि के लिए पीडियाट्रिक केयर ट्रेनिंग भी शुरू हो चुका है। यह कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। सुविधानुसार भौतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

भाजपा नेता बीएल संतोष ने कहा- जन-जन को बताएं मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियां

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मिशन-2022 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है। बीते 31 मई को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राजधानी लखनऊ पहुंचकर योगी आदित्यनाथ सरकार और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठककर उनके काम-काज की समीक्षा की और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के मंत्र दिए।

पहले दिन भाजपा कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा के बाद बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और डॉ. दिनेश शर्मा समेत तमाम मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों और लखनऊ क्षेत्र के विधायकों और सांसद के साथ एक-एक कर बैठक की है। इस दौरान कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों की जानकारी लेकर सरकार और संगठन के काम-काज और आपसी समन्वय जैसे तमाम मुद्दों पर भी उनका फीडबैक लिया।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लखनऊ प्रवास के तीसरे व आखिरी दिन मीडिया व आइटी सेल के पदधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों से सवाल-जवाब भी किया। बैठक के दौरान उनका जोर केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों और अछे कार्यों व संगठन के सेवा कार्यों की जानकारी सुलभता से लोगों तक पहुंचाने पर रहा। उन्होंने कहा कि यह दोनों ही विभाग सरकार और संगठन की इमेज बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपसी सामंजस्य व समन्वय से इसे और भी बेहतर किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश प्रवास के तीसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने मीडिया व आईटी सेल के पदधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों से सवाल-जवाब भी किया। बैठक के दौरान उनका जोर मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियों और अछे कार्यों व संगठन के सेवा कार्यों की जानकारी सुलभता से पहुंचाने पर रहा। कहा कि यह दोनों ही विभाग सरकार व संगठन की इमेज बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपसी सामंजस्य व समन्वय से इसे और भी बेहतर किया जा सकता है।

उन्होंने सभी पदाधिकारियों से इस संबंध में फीडबैक भी लिया, साथ ही और सृजनात्मक ढंग से आमजन को नीतियों के प्रति आकर्षित करने के संबंध में नए सुझावों पर भी अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष की नकारात्मक टिप्पणियां बढ़ेंगी। उनकी ओर से सरकार की मनगढ़ंत तीखी अलोचना की जाएगी, इनका तर्क के साथ उचित जवाब भी दिया जाना चाहिए।

बैठक में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, भाजपा के प्रदेश मीडिया इंचार्ज मनीष दीक्षित प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, हीरो वाजपेयी, मनीष शुक्ला, प्रदेश मीडिया सहप्रभारी हिमांशु दुबे, आलोक अवस्थी तथा मीडिया सहसम्पर्क प्रमुख अभय सिंह और आइटी टीम की बैठक अंकित चंदेल, कामेश्वर मिश्रा, सौरभ मरोडिया आदि उपस्थित रहे।

यूपी मदरसा मदरसा बोर्ड की भी नहीं होंगी परीक्षाएं, कक्षा एक से हाईस्कूल तक के सभी बचे होंगे प्रमोट

लखनऊ । कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तहतानिया व फौकानिया (कक्षा 1 से 8 तक) के सभी करीब 16 लाख बचे प्रमोट किए जाएंगे। मुंशी/मौलवी (हाईस्कूल) के भी बचे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की तर्ज पर प्रमोट किए जाएंगे। बोर्ड जल्द ही इसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजेगा। साथ ही मदरसा बोर्ड ने मुंशी/मौलवी के छात्रों की अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षा के अंक मंगाए हैं। वहीं, आलिम (इंटरमीडिएट) के मसले पर यूपी बोर्ड का निर्णय आने के बाद मदरसा बोर्ड फैसला करेगा।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। यूपी बोर्ड ने भी बचों की सुरक्षा देखते हुए हाईस्कूल परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया था। सीबीएसई ने कक्षा 12 की परीक्षा इस साल नहीं करने का फैसला लिया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मदरसा बोर्ड ने भी इस बार बोर्ड की परीक्षाएं न कराने का निर्णय किया है। प्रदेश के करीब 16 हजार मदरसों में तहतानिया व फौकानिया की गृह परीक्षाएं भी इस बार नहीं होंगी। बोर्ड ने सभी बचों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है।

मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड की तरह सेकेंडरी (मुंशी/मौलवी) की परीक्षाएं इस साल नहीं कराई जाएंगी। इन सभी छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम पिछली परीक्षाओं के अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड जल्द ही प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। इस बार 98 हजार छात्र-छात्राओं ने सेकेंडरी के लिए फार्म भरे हैं। जिस प्रकार यूपी बोर्ड हाईस्कूल के छात्रों को प्रमोट कर रहा है उसी प्रकार मदरसा बोर्ड भी छात्रों को प्रमोट करेगा। यदि किसी छात्र ने अर्धवार्षिक एवं प्रीबोर्ड की परीक्षा नहीं दी है तो भी उन्हें केवल प्रमोट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

यूपी ने पांच करोड़ कोरोना टेस्टिंग कर बनाया कीर्तिमान, 24 घंटे में मिले सिर्फ 1514 पॉजिटिव केस

लखनऊ । उत्तर प्रदेश ने कोरोना टेस्टिंग में नया कीर्तिमान कायम कर लिया है। प्रदेश में अब तक पांच करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही एक दिन में 3.32 लाख टेस्ट करने वाला यह पहला राय बन गया है। जो राय दूसरे नम्बर पर हैं वे डेढ़ करोड़ टेस्ट कम हैं। प्रदेश में शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जांच की जा रही है। अब हर दिन सवा तीन लाख से लेकर साढ़े तीन लाख के बीच लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3.3 लाख लोगों की कोरोना जांच के साथ ही अब तक हुए कुल टेस्ट का आंकड़ा पांच करोड़ के पार पहुंच गया। प्रदेश के लिए एक और राहत की खबर यह है कि कोरोना रिकवरी रेट 97.1 फीसद तक पहुंच गया है। राय में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 1514 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। राय में इस वक्त एक्टिव केसों के संख्या 30 हजार से भी कम है।

देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और यहां अब तक 3.5 करोड़ लोगों की कोरोना जांच की गई है। वहीं तीसरे नंबर पर कर्नाटक में तीन करोड़, चौथे नंबर पर तमिलनाडु में 2.8 करोड़ और पांचवें नंबर पर गुजरात में 2.2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। फिलहाल यूपी में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फार्मूले का प्रयोग किए जाने के कारण अब संक्रमण धीरे-धीरे काबू में आ रहा है। सीएम योगी ने अग्रेसिव टेस्टिंग, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन सिस्टम, गांवों में निगरानी समितियों के द्वारा किये गए माइक्रो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट से कोरोना नियंत्रण की रणनीति बनाई और अब ये काफी कारगर नजर आ रही है।

कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बहुत अछी हो रही है। सतत प्रयासों से अब पूरे प्रदेश में एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 30 हजार से भी कम हो चुकी है। वर्तमान में 28,694 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। अब तक 16 लाख 44 हजार 511 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट 97.1 फीसदी हो गया है।

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ट्रेसिंग-टेस्टिंग के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ से ही एग्रेसिव होने की नीति अपनाई है। यही कारण है कि आज प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। विगत 24 घंटे में कुल 3,31,511 टेस्ट किए गए, जबकि 1514 नए केस की पुष्टि हुई है और 4,439 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।

सीएम योगी के निर्देशन में निरीक्षण में एग्रेसिव, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाई गई है। 90 हजार से यादा गांवों में निगरानी समिति ट्रेस कर रही है। यदि थोड़े भी लक्षण हैं तो टेस्ट कराया जा रहा है। देश मे प्रतिदिन सब से यादा टेस्ट यूपी में हो रहा है।

किसानों के लिए दुकानें खुली हैं। आवागमन को नियंत्रित किया गया है। पिछले 25 दिनों में एक्टिव मामले 93 फीसदी कम हो गए है। देश के कई प्रदेशों में टीकाकरण बंद है लेकिम उत्तर प्रदेश टीकाकरण अभियान 1 जून से बड़े पैमाने चलाया गया है। इस महीने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

सीएम नीतीश पर फिर हमलावर हुई लालू की बेटी रोहिणी, सुशील मोदी को भी कह डाला बरसाती मेंढक

पटना । राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहीं हैं। बुधवार को भी उन्होंने ट्वीट कर राज्य सरकार व खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। लिखा कि वे खुद से पूछें कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी के काबिल हैं जब बिहार नहीं संभल रहा तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते रोहिणी ने भारतीय जनता पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हाफ पैंट वाला बरसाती मेंढक करार दिया। बुधवार को आने ट्वीट में रोहिणी आचार्या ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा है कि वे दिल पर हाथ रख कर खुद से पूछें कि

क्या वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के काबिल हैं जब बिहार नहीं संभल रहा है तो अपनी अंतरात्मा को जगा कर कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते

सुशील मोदी को बताया बरसाती मेढ़क- रोहिणी ने इसके पहले एक और ट्वीट में सिवान में एंबुलेंस घोटाले की बात कहते हुए सुशील मोदी पर भी हमला किया। उनका नाम लिए बिना लिखा कि दूसरे को आईना दिखलाने वाले तथा दिन-रात मीडिया में श्री लालू चालीसा जपने वाले की नजर अपनी ही सरकार के घोटाले पर नहीं पड़ती। इसपर वे मोनी बाबा बन जाते हैं। उन्होंने लिखा कि लालू राज में एंबुलेंस का चक्का पंक्चर हो जाने पर भी यह हाफ पैंट वाला बरसाती मेंढक मीडिया से लेकर कोर्ट तक कागज का पुलिंदा लहराते घूमता रहता था। विदित हो कि यह मामला सिवान में एमएलए और एमएलसी फंड से एंबुलेंस की खरीदारी से जुड़ा है। कुछ एंबुलेंस एमएलसी टुन्ना पांडेय के फंड से तो कुछ तत्कालीन विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और व्यासदेव प्रसाद के फंड से खरीदे गए हैं। रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने आरोप लगाया है कि सात लाख रुपये ऑन रोड कीमत वाले एंबुलेंस 22 लाख में खरीदे गए हैं।

पटना का मीठापुर बस स्टैंड 15 जुलाई से हो जाएगा बंद, अब गाड़ी पकड़ने को तय करनी होगी अधिक दूरी

पटना । बिहार की राजधानी पटना में स्थित मीठापुर बस स्टैंड 15 जुलाई से पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसकी जगह सभी यात्री बसें बैरिया स्थित नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेंगी। बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। इस फैसले के लागू होने के बाद पटना जंक्शन से बस स्टैंड की दूरी दोगुना से अधिक हो जाएगी। वहीं पाटलिपुत्र जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर ट्रेन छोड़ने-पकड़ने वाले लोगों को भी अब बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी।

20 जून तक बस टर्मिनल के निकट पुलिया के निर्माण का निर्देश

उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया कि 15 जुलाई से पूर्व जीरो माइल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के संपर्क पथ के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लें। इसके साथ ही बस टर्मिनल के निकट पुलिया का निर्माण भी 20 जून तक कर लें। बुडको के प्रबंध निदेशक को मानूसन में भी निर्बाध रूप से काम जारी रखने के लिए वहां पर ट्रॉली माउंटेड पंप की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

नए बस टर्मिनल से फिलहाल जहानाबाद और गया जिले की बसों का परिचालन हो रहा है। प्रधान सचिव ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि 15 जून से नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई की यात्री बसें भी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से संचालित करने की आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लें। इसी प्रकार धीरे-धीरे 15 जुलाई से सभी जिलों की बसों को नए बस स्टैंड से संचालित करने का प्लान बना लें।

अफसरों को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के प्रथम तल की भांति भू-तल पर भी शौचालय, यूरिनल और पेयजल की सुविधा देने का निर्देश भी अफसरों को दिया गया है, ताकि आम यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

प्रधान सचिव ने कहा कि पटना राजधानी होने को साथ साथ प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, आर्थिक गतिविधियों एवं चिकित्सा सुविधा का भी केंद्र है। राज्य के विभिन्न जिलों के साथ अन्य राज्यों से आम नागरिकों का बसों के माध्यम से भी काफी आवागमन होता रहता है।

भदोही में ब्यूटी पार्लर से महिला बनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, घूंघट उठाया तो उड़े होश

भदोही । गोपीगंज नगर से सटे एक गांव में मंगलवार को दोपहर बाद दुस्साहसिक तरीके से सहेली बनकर युवती के वेश में प्रेमिका से मिलने प्रेमी घर में घुस गया। प्रेमिका से मुलाकात भी करने में सफल रहा। अंजान महिला को देख घर की महिलाओं को आशंका हुई और वह घूंघट उठाने को कहने लगी। मौके की नजाकत भांप वह बाहर निकलने लगा तो महिलाओं ने दबोच लिया। इस दौरान जब महिलाओं ने उसका बाल पकड़ा तो वह उनके हाथ में आ गया और युवक फरार होने में सफल रहा।

दोपहर बाद एक युवक पूरी तरह से महिला का रूप बदलकर पड़ोस के चाय-पान बेचने वाले के घर में घुस गया। घूंघट की ओट में अचानक अनजान महिला को घुसते देख परिवार की महिलाएं सक्रिय हो उठी। बाहर दुकान पर बैठे लोगों को अंदर बुला लिया तो पूछताछ के दौरान युवक की पोल खुल गई। अंदर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। हालांकि, बीच-बचाव करते हुए उसे बाहर ले आया गया। जहां उससे घर में घुसने का कारण पूछा ही जा रहा था कि वह बाइक लेकर खड़े दो युवकों के साथ भाग निकला। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि युवक पड़ोस की युवती से प्रेम करता था। प्रेमिका से मिलने के लिए वह यह नायाब तरीका निकाला था। मुलाकात करने के लिए वह पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गया था। पार्लर में सजने के बाद प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था।

परिजनों के अनुसार युवक ने महिला का रुप धरकर घर में प्रवेश किया और गुपचुप युवती से बात करने लगा। परिवार के लोगों को अनजान महिला के घर में घुसकर इस तरह घूंघट में जाने को लेकर शंका हुई तो पूछताछ में शंका यकीन में बदल गया। आनन-फानन युवती को घर के अंदर करके युवक का बाल खींचा गया तो वह बाहर निकल गया। इसके बाद साड़ी खींचकर युवक को उजागर करने का प्रयास जबतक किया जाता, तब तक बाहर खड़े दोस्तों की बाइक पर वह तेजी से बैठकर फरार हो गया। जब तक लोग उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करते, तब तक वह बाइक से आंखों से ओझल हो चुका था।

दोस्तों ने बनाया था मिलन का प्लान- परिजनों ने युवती से पूछा तो पता चला कि प्रेमी के दोस्तों ने लॉकडाउन में दूरी की वजह से मिलने का इस तरह प्लान बनाया था। पकड़े जाने पर घर के बाहर दोस्त बाइक लेकर तैयार खड़े थे। आनन-फानन मामला मिलने के बाद उजागर हुआ तो परिजनों और पड़ोसियों ने युवक का चेहरा उजागर कर पिटाई शुरू की तो साड़ी में ही युवक मौके से लोगों से बचकर तेजी से फरार हो गया। युवती ने बताया कि किसी को शक न हो इसलिए उसके दोस्तों ने उसे ब्यूटी पार्लर से पूरी तरह महिला का साज श्रृंगार करके बुला रखा था। हालांकि, चाल ढाल और घूंघट को लेकर शक होने के बाद मामला घर में ही मामला पकड़ में आ गया। आनन फानन उसे पकड़ कर बाहर बरामदे में ले जाया गया और उसका इस दौरान किसी ने वीडियो भी बना लिया। अब इस मामले का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के राजभवन में राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन को जन्मदिन की बधाई दी।

कोयंबटूर में कोविड तालाबंदी के दौरान घरेलू गैस आपूर्ति करने वाले पुरुष दोपहिया वाहन पर सिलेंडर के साथ सवारी करते हैं।

मुंबई के बोरीवली पूर्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए।

एक नजर

पाजिटिविटी दर गिरकर हुई 6.57 फीसद, लगातार 20 दिन से रोजाना ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक

नई दिल्ली । देश में कोरोना की दूसरी लहर के लगातार मंद पड़ने के साथ पाजिटिविटी दर में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में देश में जहां 1.32 लाख मामले सामने आए वहीं पाजिटिविटी दर घटकर 6.57 फीसद हो गई है। पिछले नौ दिनों से पाजिटिविटी दर 10 फीसद से कम बनी हुई है। इसके साथ ही साप्ताहिक पाजिटिविटी दर भी घटकर 8.21 फीसद हो गई है। इसी के साथ नए मामलों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या लगातार 20वें दिन जारी रही। पिछले 24 घंटों में 2,31,456 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए। इस तरह अब तक 2.61 करोड़ लोग इस बीमारी को हरा चुके हैं। इस दौरान कोरोना से जिन 3,207 लोगों ने दम तोड़ा उनमें 854 लोग महाराष्ट्र के थे। इसके अलावा तमिलनाडु से 490, कर्नाटक से 464, केरल से 194, उप्र से 175 बंगाल से 137 और आंध्र प्रदेश से 104 लोग शामिल हैं। इसी तरह अब तक कुल कोरोना से जान गंवाने वाले 3,35,102 लोगों में सर्वाधिक 96,198 लोग महाराष्ट्र के रहे। वहीं कर्नाटक के 29,554, तमिलनाडु के 24,722, दिल्ली के 24,299, उप्र के 20,672, बंगाल के 15,678, पंजाब के 14,649 और छत्तीसगढ़ के 13,077 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजस्थान के भरतपुर में पुलिस जैसा सायरन बजा तो शादी में भगदड़ मची, 3 बच्चे कुएं में गिरे

जयपुर। राजस्थान में शादियों में ज्यादा लोगों के जुटने को लेकर सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। सख्ती के चलते भरतपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, भरतपुर जिले के अगरवाली गांव में मंगलवार रात एक शादी थी, जिसमें 500 से अधिक लोग शामिल हुए। लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे कि अचानक पुलिस की गाड़ी जैसा सायरन बज उठा। सायरन की आवाज सुनकर लोग तेजी से इधर-उधर भागे। भगदड़ के बीच तीन बच्चे अंधेरे के कारण एक खुले में गिर गए। इनमें से दो बच्चे नीचे जा गिरे और एक बच्चे ने पाइप पकड़ लिया । पाइप पकड़ने वाला बच्चा वहीं लटक गया। लोगों ने तत्काल रोशनी का इंतजाम किया और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों की जान बच गई। शादी में शामिल लोग बच्चों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए,लेकिन वहां चिकित्सक ने भरतपुर जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। बुधवार को बच्चों को इलाज चल रहा है। तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है । ग्रामीणों का कहना है कि लोग शादी के जश्न में व्यस्त थे कोई डीजे पर नाज रहा था तो कोई भोजन कर रहा था। इसी बीच गांव से पुलिस जैसा सायरन बजाते हुए गाड़ी निकली तो लोगों में दहशत फैल गई और भगदड़ में तीन बच्चे में गिर गए थे, जिन्हे बाहर निकाल लिया गया। कामां पुलिस ने शादी के आयोजक के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया है ।

शादी में 11 से ज्यादा लोग जुटे तो 1 लाख का जुर्माना होगा- कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। दूसरी लहर के बीच अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है । कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने शादियों,सामाजिक,धार्मिक व राजनीतिक समारोह के आयोजन पर रोक लगा रखी है । शादियों के आयोजकों के खिलाफ 1 लाख रूपए का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है । इस संबंध में गृह विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की । शादी की सूचना नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 1 लाख और बारात के आगावगम में साधनों के उपयोग होनने पर मालिक के खिलाफ 1 लाख का जुर्माना किया जाएगा । शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग उपखंड अधिकारी व संबंधित पुलिस थाने में देनी होगी।

प्रेमी की मदद से की पति की हत्या, रसोई में दफनाया शव; मामला दर्ज

मुंबई । मुंबई के दहिसर, पूर्व इलाके से एक चौंका देने वाली घटना सामने आयी है। यहां एक 28 वर्षीय महिला ने अपने प्रेमी की मदद से कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को रसोई में ही दफना दिया। मुंबई पुलिस के अनुसार इस घटना की जानकारी मृतक की 6 वर्षीय बेटी द्वारा अपने चाचा को दी जिसके बाद शिकायत दर्ज करवायी गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है जबकि हत्या में शामिल उसका प्रेमी अभी फरार है।

पुलिस के अनुसार महिला की पहचाना राशिदा शेख के तौर पर हुई है, जबकि उसके प्रेमी की पहचान अमित मिश्रा के रूप में हुई है। इस मामले की आरोपी महिला राशिदा को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन उसका प्रेमी फरार है। ये घटना दहिसर (पूर्वी) के रावल पाडा इलाके में 12 दिन पहले हुई थी, आरोपी महिला ने अपने प्रेमी की मदद से अपनी नाबालिग बेटी के सामने ही पति रईस शेख की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने मिलकर शेख के शव को घर की रसोई में ही दफन कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शेख कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने जब उसे बीते 7 दिनों से नहीं देखा तो 25 मई को इस मामले में पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। ये मामला तब सामने आया जब शेख का भाई उसके घर आया और उसकी भतीजी ने हत्या के बारे में सारी बात अपने चाचा को बता दी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कर शव को जब्त कर लिया।

मुंबई में प्री-मानसून ने दी दस्तक, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

मुंबई । मुंबईवासियों को जल्द ही गर्मी से निजात मिलने वाली है। यहां मंगलवार शाम को प्री-मानसून बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई में हो रही प्री-मानसून बारिश को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 जून तक मानसून आ जाएगा। वहीं केरल में मानसून 1 जून को पहुंचना था लेकिन अब 3 जून को पहुंचने की उम्मीद जतायी जा रही है। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में मंगलवार शाम 7 बजे से बारिश शुरू हुई। जबकि कुछ इलाकों में इससे पहले ही बारिश शुरू हो गई, हालांकि यह तेज बारिश नहीं थी। एक अधिकारी ने कहा, अंधेरी, जोगेश्वरी, डिंडोशी, गोरेगांव, मलाड और बोरीवली (सभी उपनगरों) में मंगलवार शाम को बारिश शुरू हुई और यह देर रात तक जारी रही। उन्होंने कहा कि कोलाबा और भायखला सहित दक्षिण मुंबई के इलाकों में तुलनात्मक रूप से कम बारिश हुई। पिछले महीने चक्रवात तौकते के बाद हुई भारी बारिश के बाद शहर में आर्द्रता के स्तर में वृद्धि देखी गई। लगभग एक सप्ताह तक तापमान बढ़ने से आर्द्रता बढ़ गई। लेकिन प्री मानसून की बारिश से आने वाले दिनों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा। गौरतलब है कि मुंबई में न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था लेकिन इसके बावजूद दिन औ रात के तापमान में महज 5 डिग्री का अंतर था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, कब- कब वैक्सीन खरीदी, पूरी डिटेल बताएं

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण नीति पर अपनी सोच को दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी कोविड टीकों के खरीद इतिहास को देखते हुए पूरे डेटा को रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 जून तक तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने टीकाकरण अभियान के पहले तीन चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीका लेने वाली (एक डोज और दोनों डोज के साथ) आबादी के प्रतिशत पर आंकड़ा मांगा है। इसमें टीका लगवाने वाली शहरी आबादी की तरह टीका लगवाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के साथ आंकड़े मांगे हैं। केंद्र सरकार को अब तक के सभी तरह की कोरोना वैक्सीन की खरीदारी को लेकर भी जानकारी देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 09 मई के हलफनामे में कहा है कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी आबादी को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करेगा।

यह महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस न्यायालय के समक्ष इस स्थिति की पुष्टि/अस्वीकार करें। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि हम प्रत्येक राज्य सरकारों को 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जहां वे अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और अपनी व्यक्तिगत नीतियों को रिकॉर्ड में रखेंगे।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि उन्होंने (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) अपनी आबादी का मुफ्त में टीकाकरण करने का फैसला किया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि यह नीति उनके हलफनामे के साथ संलग्न की जाए ताकि उनके क्षेत्रों के भीतर की आबादी को राज्य टीकाकरण केंद्र में मुफ्त में टीकाकरण के अधिकार का आश्वासन दिया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्टेप 1, 2 और 3 में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करना है, इसके लिए केंद्र द्वारा एक रूपरेखा दायर की जानी है। ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में जानकारी देने को कहा है।

मेहुल चोकसी के भाई से मुलाकात की बात से डोमिनिका के विपक्षी नेता का इनकार, कहा- पैसे देने की बात झूठी

नई दिल्ली । भारत के बैंकों के साढ़े 13 हजार करोड़ रुपये लूट कर फरार वाले मेहुल चोकसी पर आज फैसला आएगा। इस बीच मेहुल चोकसी के भाई चेतन चोकसी से मुलाकात पर डोमिनिका के विपक्षी नेता ने सफाई दी है। डोमिनिका के विपक्ष के नेता लेनोक्स लिंटन ने चेतन चोकसी से मुलाकात की बात से इनकार कर दिया है। लिंटन ने कहा कि मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी कोई पैसा नहीं मिला है।विपक्ष के नेता लेनोक्स लिंटन ने चेतन चोकसी से मुलाकात की बात से इनकार करते हुए कहा- हम मेहुल चोकसी और उसके सहयोगी और यहां तक ??कि उसके परिवार के सदस्यों से भी नहीं मिले हैं। हम उन्हें नहीं जानते। उनके लिए चुनाव प्रचार या किसी अन्य चीज के लिए हमें कोई धन उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह बिल्कुल झूठ है।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रकाशन इस क्षेत्र की कुछ सरकारों के पासपोर्ट बेचने वाले मित्रों से जुड़ा होना चाहिए। मुझे किसी से एहसान

के बदले में या उन चीजों के परिणामस्वरूप कोई पैसा नहीं मिला है जो मैंने किया है या नहीं किया है या करने या न करने का वादा किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं चेतन चोकसी (मेहुल का भाई) को नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने चेतन चोकसी से या उसके साथ कभी बात नहीं की, मुझे लगता है कि समथिंग टाइम्स नामक प्रकाशन से एक ऑनलाइन कहानी आ रही है, मैंने इस वेबसाइट को कभी नहीं देखा है।

डोमिनिका स्थित एक समाचार आउटलेट-एसोसिएट टाइम्स ने मंगलवार को रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बड़े भाई चेतन चीनू भाई चोकसी ने डोमिनिका के नेता प्रतिपक्ष लेनोक्स लिंटन से मुलाकात की थी और इन दोनों के बीच यह समझौता हुआ था कि टोकन धन और चुनावी चंदे के वादे के बदले विपक्षी नेता संसद में चोकसी के मामले को उठाएंगे। समाचार आउटलेट ने दावा किया कि चेतन 29 मई को एक निजी जेट से डोमिनिका आया था और अगले दिन मैरीगोट में लिंटन से मिला था।

क्या मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकेगा। भारतीय समयानुसार आज शाम 6.30 बजे डोमिनिका की अदालत में इसे लेकर सुनवाई होनी है। इसमें उसके प्रत्यर्पण को लेकर कोई फैसला आ सकता है। भारत आज कोर्ट में चोकसी को लेकर कई सबूत पेश करेगा।

राजस्थान में प्रारंभ हुई अनलॉक की प्रक्रिया, 24 घंटे में मिले 1276 नए संक्रमित, 65 की मौत

जयपुर । कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते 23 दिन बाद राजस्थान में बंद पड़े बाजार बुधवार से खुले । व्यासायिक गतिविधियां प्रारंभ हुई । सुबह 6 से 11 बजे तक सभी दुकानें खुली । राजस्थान सरकार ने 10 मई को सख्ती लॉकडाउन लागू किया था । इससे पहले भी कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन लागू था । इस तरह करीब डेढ़ माह बाद बुधवार को पूरी तरह से बाजार खुले । अब सभी दुकानों सप्ताह में चार दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी । निजी वाहनों का आवागमन सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक होगा । वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा । इस दौरान आवश्यक सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। अनलॉक में अब एसी शॉपिंग कॉम्पलेक्स व मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेगी । बुधवार को दुकानें तो खुली,लेकिन ग्राहक नहीं पहुंचे । फल-सब्जी की दुकानें,मंडिया और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 6 से 11 बजे तक खुलना प्रारंभ हुए हैं। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुलने लगे हैं। बैंक अब दोपहर 2 बजे तक खुल रही है,पहले 12 बजे तक थी ।

सरकारी दफ्तरों में 25 फीसदी कर्मचारी पहुंचे । निजी कार्यालयों में भी कुछ कर्मचारियों को छूट दी गई । सिनेमाघर,स्विमिंग पूल,मल्टीप्लेक्स,सिटी बसें,स्कूल,कॉलेज,कोचिंग सेंटर्स और जिम फिलहाल बंद रहेंग । रोड़वेज बसों के साथ ही निजी बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा ।

उधर पिछले 24 घंटे में 1276 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही 65 लोगों की मौत हुई है ।

आंध्र प्रदेश में मार्मिक घटना, एक मां के अपने बच्चे के लिए इच्छामृत्यु की मांग के 2 घंटे के अंदर हो गई उसी बेटे की मौत

चित्तूर(आंध्र प्रदेश) । आंध्र प्रदेश में एक मार्मिक घटना सामने आई है। आंध्र प्रदेश में एक लाचार मां के अपने 9 साल के बच्चे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने के 2 घंटे बाद ही उसी बेटे की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक नौ साल के लड़के की मां की ओर से मंगलवार को अदालत में इच्छामृत्यु के लिए आवेदन करने के दो घंटे के अंदर ही एक दुर्लभ बीमारी से मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले एक दंपती के नौ साल के बेटे हर्षवर्धन को खून से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी का पता चला था। परिवार चित्तूर जिले के चौडेपल्ली मंडल के बिरजेपल्ली गांव में रहता है।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले इस दंपती का 9 साल का बेटा हर्षवर्धन खून से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित था। लाचारी के कारण इलाज न करा पाने के कारण उसकी मां ने अदालत में इच्छामृत्यु के लिए आवेदन किया था। हर्षवर्धन जब चार साल का था, तब उस गरीब दंपती को पता चला कि उनके बेटे को खून से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी है। इलाज के बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस कारण दंपती को इलाज के लिए चार लाख रुपये का कर्ज भी लेना पड़ा।

उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, अरुणा ने मंगलवार को पुंगनूर कोर्ट में आवेदन कर अनुरोध किया कि या तो सरकार को उसके बेटे की देखभाल करनी चाहिए या अदालत को उसकी इच्छामृत्यु की अनुमति देनी चाहिए। दुर्भाग्य से, याचिका दायर करने के मुश्किल से दो घंटे के भीतर उस बच्चे ने अदालत से गांव जाते समय अंतिम सांस ली। ऐसी घटनाएं मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली हैं। एक मां ने अपने ही बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग की लेकिन उससे पहले ही बेटे की मौत हो गई।

भारतीय कंपनियों से साइबर अपराधियों ने वसूली तीन गुना फिरौती

मुंबई । भारतीय कंपनियों पर रैंसमवेयर के हमले बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभी तक कंपनियां डाटा को अनलॉक करने के लिए फिरौती के तौर पर साइबर अपराधियों को तीन गुना रकम दे चुकी हैं। विभिन्न देशों की कंपनियों पर हो रहे रैंसमवेयर पर वैश्विक साइबर सिक्योरिटी कंपनी सोफोस ने स्टेट आफ रैंसमवेयर-2021 के नाम से रिपोर्ट बनाई है।इसके मुताबिक इस वर्ष भारत उन 30 देशों की सूची में अव्वल है, जहां कंपनियों पर सबसे ज्यादा रैंसमवेयर हमले किए गए हैं।

फिरौती के बाद भी नहीं मिलता पूरा डाटा- रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों द्वारा फिरौती देने के बाद भी उन्हें सिर्फ 75 फीसद डाटा ही वापस मिलता है। सिर्फ चार फीसद ऐसी कंपनियां हैं, जिन्हें अपना पूरा डाटा मिलता है।

सर्वे में भारत सहित 30 देशों के प्रमुख लोग - सर्वे में यूरोप, अमेरिका, एशिया- प्रशांत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के

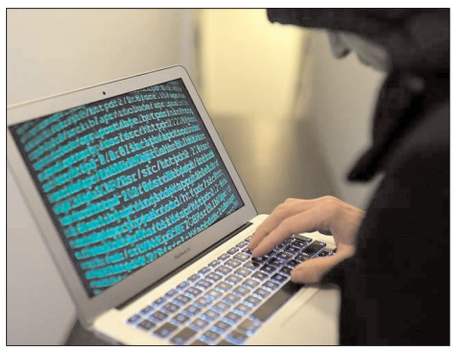

30 देशों के 5400 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। ये सभी लोग विभिन्न कंपनियों के नीति निर्माताओं में शामिल हैं। सर्वे में भारत के 300 लोगों से विभिन्न प्रश्नों के जवाब मांगे गए।

86 फीसद कंपनियों को हमले का अंदेशा- पिछले 12 महीनों के दौरान जिन भारतीय कंपनियों पर रैंसमवेयर का हमला नहीं हुआ है, उनमें से 86 फीसद का मानना है कि भविष्य में वह इसकी जद में आ सकती हैं। ऐसी 57 फीसद कंपनियों का कहना है कि रैंसमवेयर हमलों को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि साइबर हमले के लिए नित-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।

सोफोर इंडिया और सार्क के मैनेजिंग डायरेक्टर, सेल्स सुनील शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले रैंसमवेयर से प्रभावित होने वाली कंपनियों में गिरावट आई है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारतीय कंपनियों के प्रभावित होने की संभावना अधिक है। इस तरह के हमले कंपनियों के बजट को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। 86त्न भारतीय कंपनियों का मानना है कि साइबर हमले रोक पाना उनकी आइटी टीम के बस में नहीं है। हालांकि, वैश्विक आंकड़ा 54 फीसद का है।

सनकी पति ने पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की, 6 माह के बच्चे को भी नहीं बख्शा

जयपुर। राजस्थान में कोटा जिले रामपुरा पुलिस थाना इलाके में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी । उसने अपने 6 माह के बेटे को भी नहीं छोड़ा । कुल्हाड़ी के वार के कारण बच्चे के दाएं हाथ के नीचे छाती पर चोट लगी, जिसे स्थानीय जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया । बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई । जानकारी के अनुसार आरोपित पति सुनील वाल्मीकी अपनी 35 वर्षीय पत्नी पर शक करता था । इस कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था । मंगलवार रात भी दोनों के बीच तकरार हुई । इसी दौरान सुनील ने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया । मृत पत्नी को वह घर से 80 मीटर दूर तक गली में खींचता हुआ ले गया । यह दृश्य देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई । इसके बाद वह पत्नी को बीच सड़क पर छोड़कर कुल्हाड़ी लेकर पुलिस थाने पहुंचा । उसने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को बताया कि मैंने मेरी पत्नी को इस कुल्हाड़ी से मार दिया । इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सीमा का शव सड़क पर पड़ा हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि सुनील दुष्कर्म के मामले में 7 साल की सजा काट कर कुछ माह पहले ही बाहर आया था । पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों पति-पत्नी अपने दो बच्चों के साथ मंगलवार शाम रिश्तेदार के घर गए थे,वहां से देर शाम वापस लौटे । 5 साल का बड़ा बेटा अपनी नानी के घर चला गया । इसके बाद दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और सुनील ने सीमा की हत्या कर दी ।

गुजरात सरकार का 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला, 7 जून से ऑनलाइन शैक्षिक सत्र होगा शुरू

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। आगामी 7 जून से ऑनलाइन शैक्षिक सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सीबीएसई की परीक्षा कोरोना के चलते रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए गुजरात बोर्ड की परीक्षा भी इस साल नहीं लेने का फैसला किया गया। मंगलवार शाम को राज्य सरकार ने बारहवीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया था लेकिन केंद्र सरकार के परीक्षा नहीं लेने के फैसले को देखते हुए राज्य सरकार ने भी उसका अमल किया।

शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चूड़ास्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के अनुसार ही गुजरात सरकार काम करेगी। महामारी के चलते छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने इससे पहले 1 जून से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं लेने का एलान किया था तथा मंगलवार शाम को ही परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून से अगला शैक्षणिक सत्र यथावत शुरू होगा तथा सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। गुजरात शिक्षा बोर्ड की 12वीं साइंस कॉमर्स तथा सामान्य वर्ग की परीक्षाएं ली जानी थी लेकिन अब यह भी रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले सरकार ने दसवीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा है कि सरकार ने फैसले में देरी कर बच्चों को मानसिक तनाव में रखा। सरकार ने परीक्षा लेने के अपने फैसले को 20 घंटे में ही बदल लिया जो बताता है कि राज्य सरकार अपने निर्णय पर अडिग नहीं है। सरकार की असमंजस की स्थिति के कारण है छात्र-छात्राएं परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता से भारी तनाव में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से आग्रह किया है कि 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद अब छात्र छात्राओं को अंकतालिका उपलब्ध कराकर उनकी अगली कक्षा में प्रवेश के लिए जल्द व्यवस्था करनी चाहिए।

एलोपैथी के साथ आयुर्वेद दवा देने से शीघ्र स्वस्थ हुए कोरोना मरीज, 8 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव

अहमदाबाद । एलोपैथी के साथ आयुर्वेद की दवाओं से कोरोना मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने का दावा गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने किया है। सिविल अस्पताल में मरीजों के दो समूह पर किये गये प्रयोग से पता चला कि एलोपैथी के उपचार से जहां कोरोना संक्रमित को निगेटिव होने में 12 दिन लगे वहीं एलोपैथी के साथ आयुर्वेद की दवाएं देने से 8 दिन में मरीज निगेटिव आये साथ ही किसी मरीज को आईसीयू की जरूरत भी नहीं पडी। कोरोना महामारी के दौरान कई तरह के शोधकार्य हुए लेकिन अहमदाबाद में 1200 बेड की स्पेशल कोविड-19 सिविल अस्पताल में एलोपैथी के साथ अखंडानंद आयुर्वेदिक अस्पताल के आयुर्वेद चिकित्सकों की दवा देकर उपचार का अनोखा तरीका अपनाया गया। कोरोना संक्रमित 26 मरीजों के दो समूह बनाये गये, एक समूह को सिर्फ एलोपैथी की दवाएं दी गई जबकि दूसरे समूह को एलोपैथी के साथ आयुर्वेद की दवाएं भी दी गई। मेडिकल विशेषज्ञ समिति की देखरेख में एक प्रमाणिक प्रोटोकोल के तहत स्वास्थ्य मंत्री नीतिन पटेल व विभाग की प्रधान सचिव डॉ जयंती रवि की मंजूरी से यह उपचार चला तथा इसके परिणाम चौंकाने वाले रहे। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद की दवाओं से मरीज जल्द स्वस्थ हुए साथ ही उन्हें उपचार के दौरान किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई व आईसीयू की भी जरूरत नहीं पड़ी। झ्रस्टेंडर्ड ट्रीटमेंट ग्रुप एसटीजी का सिर्फ एलोपैथी पद्धति से उपचार किया गया जबकि आयुर्वेद ट्रीटमेंट ग्रुप एटीजी को एलोपैथी के साथ आयुर्वेद की दवाएं भी दी गई। इनमें दशमूल क्वाथ, पथ्यादि क्वाथ, त्रिकटू चूर्ण व काढा दिन में एक बार खाली पेट दिया गया। संशम वटी, आयुष टेबलेट, यष्टीमधु घनवटी चूसने की टेबलेट दी जिससे मरीज जल्द ठीक हो गये। एसटीजी ग्रुप के मरीजों का आरटी-पीसीआर 12 दिन में निगेटिव आया जबकि एटीजी ग्रुप के मरीजों का रिपोर्ट 8 दिन में ही निगेटिव आया। सिविल अस्पताल डॉ जेवी मोदी से इस संबंध में और जानकारी चाहने को कॉल किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

एक्टर नहीं आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे आर माधवन

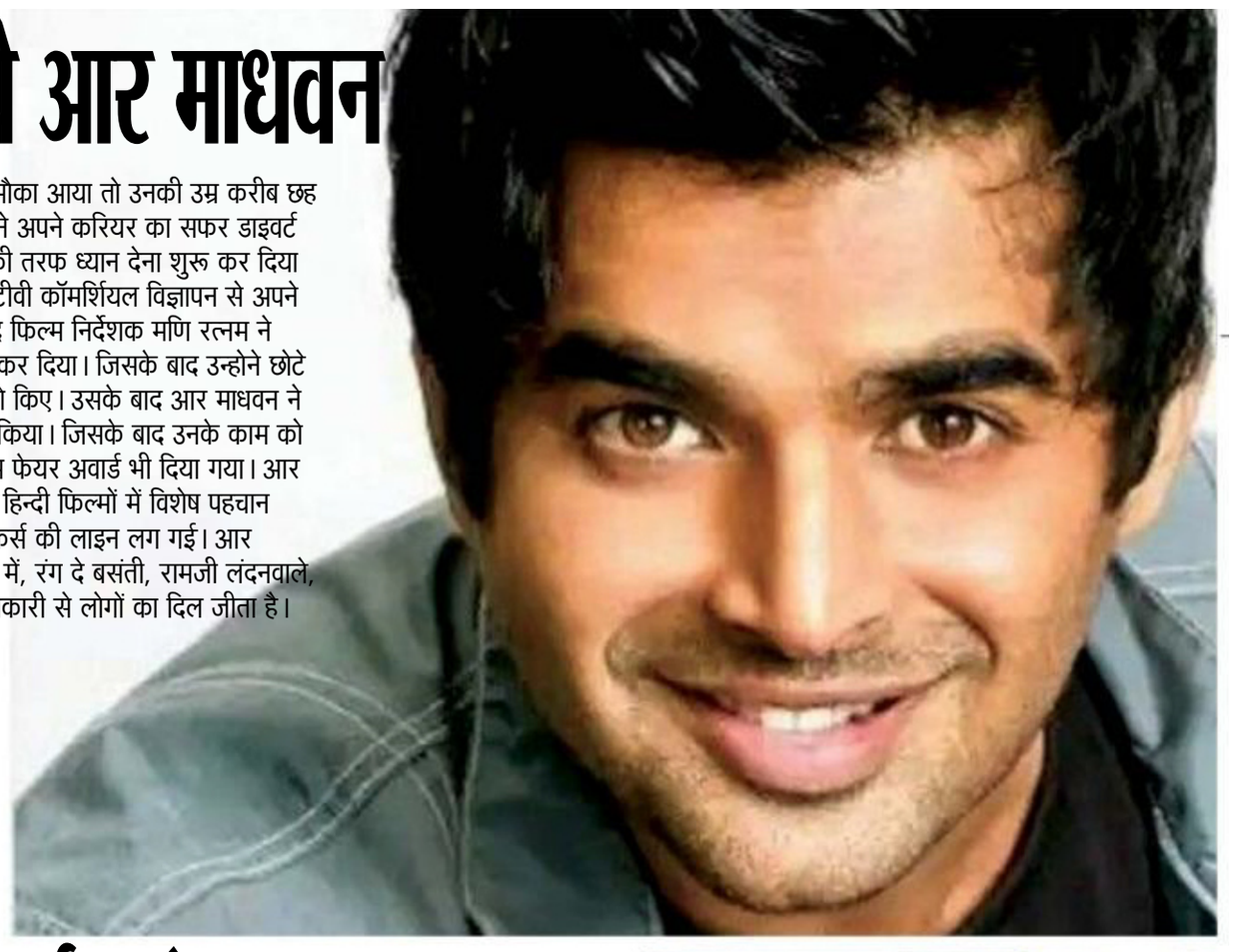

साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी अदाकारी का डंका बजा चुके एक्टर आर माधवन 1 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म बिहार के जमशेदपुर में एक तमिल परिवार में हुआ था। आर माधवन के पिता टाटा स्टील एक्सिक्यूटिव रहे हैं। साल में 1999 में माधवन ने प्रेमिका सरिता बिर्जे से विवाह किया था। उनके एक बेटा वेदांत है। आर माधवन ने 29 साल की उम्र में शादी के बाद अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और लगातार अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। आर माधवन ने भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और टीवी प्रस्तोता के तौर पर खास तौर पर अपनी पहचान बनाई है। अपनी इसी विशेष प्रतिभा के बल पर वो हिंदी सिनेमा में फिल्मफेयर पुरुस्कार जीत चुके हैं।

एक इंटरव्यू में माधवन ने इस बात का खुलासा किया था कि वे कभी भी एक अभिनेता नहीं बनना चाहते थे। उन्होने अपने मन में एक आर्मी अफसर बनने का सपना था पाल रखा था। लेकिन नियति में शायद कुछ और ही लिखा था।

जब आर माधवन के पास आर्मी में जाने का मौका आया तो उनकी उम्र करीब छह महीने कम निकल गई। जिसके बाद उन्होने अपने करियर का सफर डाइवर्ट कर दिया। अब उन्होने पब्लिक स्पीकिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। साल 1997 में आर माधवन ने एक टीवी कॉमर्शियल विज्ञापन से अपने करियर की शुरुआत की थी। जिसके बाद फिल्म निर्देशक मणि रत्नम ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया लेकिन रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद उन्होने छोटे पर्दे की ओर ध्यान दिया और कई टीवी शो किए। उसके बाद आर माधवन ने दक्षिण भारत की कई फिल्मों में अभिनय किया। जिसके बाद उनके काम को तारीफ मिलने लगी थी। उन्हें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। आर माधवन को फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिन्दी फिल्मों में विशेष पहचान मिली। इस फिल्म के बाद उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई। आर माधवन ने थ्री इडिएट्स, रहना है तेरे दिल में, रंग दे बसंती, रामजी लंदनवाले, तनु वेड्स मनु जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता है।

कार्तिक आर्यन को बड़ा झटका! या 'दोस्ताना 2' और 'फ्रेडी' के बाद एक और फिल्म से कर दिया गया बाहर?

ऐसा लग रहा है अभिनेता कार्तिक आर्यन के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले करण जौहर की 'दोस्ताना 2', फिर शाहरुख खान के प्रोडक्शन की 'फ्रेडी' से उन्हें बाहर कर दिया गया। अब जो खबर सामने आई है निश्चित रूप से उनके प्रशंसकों को निराशा होगी।

कार्तिक को झटका

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कार्तिक आर्यन के हाथों से एक और फिल्म चली गई है। जी हां, सूत्र ने बताया कि फिल्ममेकर आनंद एल राय की अनटाइल्ड फिल्म से कार्तिक आर्यन को आउट कर दिया गया है। यह एक गैंगस्टर फिल्म है लेकिन अब कार्तिक इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे।

अभी तक वजह पता नहीं

सूत्र ने कहा कि 'आनंद के साथ कार्तिक की बातचीत अगले स्तर तक पहुंच गई थी। स्क्रिप्ट को पढ़ने से लेकर उसका नैरेशन तक दे दिया गया था लेकिन इससे पहले वो फिल्म साइन करते, चीजें नहीं हुईं।' हालांकि इसके पीछे की वजह के बारे में अभी पता नहीं चला है। सूत्र ने आगे कहा कि 'फैक्ट ये है कि करण जौहर ने जब कार्तिक को निकाला तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हुए। ऐसे में यह तीसरी फिल्म है जिससे कार्तिक चूक गए।' बता दें कि इस साल फरवरी में कार्तिक आर्यन और आनंद एल राय के साथ फिल्म करने की खबर आई थी। कार्तिक को आनंद के ऑफिस के बाहर भी देखा गया था।

आयुष्मान ले सकते हैं जगह

अब बताया जा रहा है कि फिल्म में आयुष्मान खुराना हो सकते हैं। सूत्र ने कहा कि 'आनंद फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को देख रहे हैं। इससे पहले दोनों ने शुभ मंगल सावधान और शुभ मंगल ज्यादा सावधान में साथ काम किया था। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए।'

या है वजह?

रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक को जिन दो फिल्मों 'दोस्ताना 2' और 'फ्रेडी' से बाहर किया गया उसकी वजह यह थी कि वो स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग कर रहे थे। जबकि फिल्म साइन करते वत उन्होंने स्क्रिप्ट पर हामी भर दी थी।

रचनात्मक रूप से आगे बढ़ना इस समय एक चुनौती है

अभिनेत्री संजना सांघी का कहना है कि ऐसे समय में काम पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण रहा है, जब देश कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वह कहती हैं कि काम की उनके दिमाग में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है और ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती रही है। उन्होंने बताया कि 'रचनात्मक रूप से, जोन इन करना एक चुनौती रही है। एक स्क्रिप्ट पढ़ना जब मैं कार्यक्रम बना रही हूं और एक आदिवासी क्षेत्र में ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूं, यह एक ऐसी चुनौती रही है जिसका मैंने पहले अनुभव नहीं किया है। इसलिए, निश्चित रूप से ध्यान भटक रहा है।'' वह आगे कहती हैं, ''सौभाग्य से, किसी तरह पिछले लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, यह पहली बार था जब हम अपने व्यस्त कार्यक्रम से अलग-अलग शहरों में रहने और हर समय सेट पर रहने से हमने अलग अनुभव किया कि घर में बंद रहना कैसा होता है। यह कठिन था। मेरे सभी अभिनेता मित्र यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि परिवार सुरक्षित है, वे सुरक्षित है और यह उन समय में से एक है जब आप जानते हैं कि समय सही होने पर आप वापस लोटेंगे। उस पर चिंता करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित होने पर ही काम पर वापस आएं।''लोगों को महामारी से निपटने में मदद करने के लिए, संजना ने हियर टू हियर नाम से एक मानसिक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया। उन्होंने सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर भारत के दूरदराज के हिस्सों में 'प्रोटेक्ट ए मिलियन' मिशन के साथ समर्थन प्रदान किया है। संजना ने कहा, 'जब दूसरी लहर आई, तो यह पूरी तरह से स्वाभाविक लगा कि कैसे विस्तार और योगदान करना है। मैंने देखा कि हर कोई एक साथ आ रहा था और अविश्वसनीय काम कर रहा था। इस अंतर को भरने के लिए हियर टू हियर था। मुझे लगा कि इस सब के बीच, हम आपूर्ति के साथ मदद करने में सक्षम थे। ' अभिनेत्री दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' में नजर आई थी।

कोरोना के कारण ऐसी हो गई थीं मलाइका अरोरा की हालत

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा अपनी फिटनेस को लेकर जानी ताजी हैं। 47 साल की उम्र में भी मलाइका ने अपनी बॉडी को बेहद फिट रखा हुआ है। मलाइका बीते साल कोरोनावायरस की चपेट में आ गई थी। चुकी हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें काफी वीकनेस हो गई थी।

अब मलाइका ने कोरोना को हराने और इसके बाद की जर्नी फैंस के साथ शेयर की है। मलाइका ने बताया कि वह काफी निराश महसूर करती थीं और उनका वजन भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को तस्वीरों में दर्शाया है। मलाइका अरोरा ने लिखा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, ये मैं अक्सर सुनती हूं। जी हां, मैं जीवन में कई चीजों के लिए आभारी हूं। लेकिन इसमें किस्मत का बहुत छोटा रोल होता है। और आसानी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं 5 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव हुई और यह बहुत बुरा था। जो भी कोविड रिकवरी को आसान कहते है वह या तो खुशकिस्मती से बहुत अच्छी इम्यूनिटी वाला है या फिर कोविड के संघर्षों से वाकिफ नहीं। मैं इससे गुजरी हूं और यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। मलाइका ने लिखा, कोरोना ने शारीरिक रूप से मुझे तोड़कर रख दिया था। दो कदम चलना बेहद मुश्किल काम लगता था। उठना, बस अपने बिस्तर से उठना या खिड़की पर खड़े होना एक जर्नी जैसा था। मेरा वजन बढ़ गया था और कमजोर महसूस कर हो रहा था। मेरा स्टैमिना खत्म हो गया था। मैं अपने परिवार और बाकी चीजों से दूर थी। 26 सितंबर को फाइनली मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और मैं बहुत ग्रेटफुल थी कि आखिर मैंने कर दिखाया। लेकिन वीकनेस बनी रही। मैं निराश थी कि मेरा शरीर वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा जैसे मेरा दिमाग फील कर रहा था। मुझे डर था कि मुझे कभी ताकत वापस नहीं मिलेगी। मैं सोचती थी कि 24 घंटे में एक एक्टिविटी खत्म भी कर पाऊंगी या नहीं। मेरा पहला वर्कआउट बहुत खतरनाक था। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। मैं टूट गई थी लेकिन दूसरे दिन मैंने वापसी की और खुद से कहा, मैं खुद को बनाने वाली हूं। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा दिन और आगे भी। मुझे नेगेटिव हुए 32 हफ्ते हो गए हैं। मैं फाइनली पहले जैसा फील करने लगी हूं। मलाइका ने लिखा, चार अक्षरों के शब्द जिसने मुझे पुश किया, वो था ।[illegible]। एक आशा कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि मुझे फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। इसके साथ ही मलाइका ने उनका साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया है और दुनिया के जल्द रिकवर होने की प्रार्थना की है।

इंग्लैंड के उप-कप्तान बने स्टुअर्ट ब्रॉड

लंदन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम का उप-कप्तान बनाया है। उन्हें यह जिम्मेदारी सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए दी गई है। वे रेगुलर कप्तान जो रूट के डिप्यूटी के तौर पर खेलेंगे। इंग्लिश टीम आज से लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलेगी।

ब्रॉड ने करियर में 146 टेस्ट मैच खेले

ब्रॉड ने अब तक करियर में 146 टेस्ट, 121 वनडे और 56 टी-20 खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 517 विकेट लिए और 3355 रन बनाए। वनडे में ब्रॉड के नाम 178 विकेट और 529 रन हैं। टी-20 में उन्होंने अब तक 65 विकेट लिए हैं। इसके अलावा 118 रन भी बनाए हैं।

फोक्स हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से नहीं खेलेंगे

इससे पहले पिछले हफ्ते इंग्लैंड के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड ने केंट के विकेटकीपर बैट्समैन सैम बिलिंग्स और नॉटिंघमशायर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हसीब हमीद को इंग्लैंड के स्क्वॉड में शामिल किया था। सरे से खेलने वाले रेगुलर विकेटकीपर बेन फोक्स मिडिलसेक्स के खिलाफ काउंटी मैच से पहले लेफ्ट हैमस्ट्रिंग चोटिल कर बैठे। इसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया।

आईसीसी का बड़ा फैसला: वन-डे में 14 तो टी-20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें लेंगी हिस्सा

ब्राजील। आईसीसी ने वर्चुअली बैठक में वर्ल्ड कप को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब वन-डे वर्ल्ड में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। आईसीसी यह फॉर्मेट 2027 और 2031 वर्ल्ड कप में लागू करेगी। इसके अलावा अगले चक्र में चार और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कराने का भी फैसला लिया गया, जो 2023 से 2031 के बीच आठ साल के चक्र में खेली जाएगी। बता दें कि पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक खेला जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा, आईसीसी बोर्ड ने 2024 से 2031 तक के शेड्यूल की आज पुष्टि की जिसमें पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप और टी-20 विश्व कप खेला जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी फिर से आयोजित होगी। इसमें कहा गया, पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 2031 में 14 टीमें होंगी जबकि 2024-30 के बीच टी-20 विश्व कप में 20 टीमें होंगी। 2024, 2026, 2028 और 2030 में 55 मैच का टूर्नामेंट होगा।

वहीं, आठ टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और 2029 में खेली जाएगी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स 2025, 2027, 2029 और 2031 में खेले जाएंगे। आईसीसी महिला टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही तय हो चुका है। बता दें कि वर्तमान में 50 ओवरों के विश्व कप में दस टीमें होती है। इस बार टी-20 विश्व कप में 16 टीमें होंगी। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीसीसीआई को भारत में कोरोना संकट के बीच टी-20 विश्व कप की मेजबानी पर फैसला लेने के लिए 28 जून तक का समय दिया है।

पीसीएल 2021: सात जून से शुरू हो सकता टूर्नामेंट, 24 को फाइनल की उम्मीद

कराची। पाकिस्तान सुपर लीग (पीसीएल 2021) की शुरुआत सात जून से यूएई में हो सकती है। वहीं, फाइनल मुकाबला 20 के बदले 24 जून को खेले जाने की संभावना है।

पीएसएल के 14 मैच खेले जा चुके हैं

बता दें कि पीएसएल के 14 मैच पाकिस्तान में खेले जा चुके हैं लेकिन कुछ खिलाड़ियों और अधिकारियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद चार मार्च को इसे स्थगित कर दिया गया था। निलंबित लीग के बाकी बचे 20 मैच यूएई में खेले जाएंगे।

कराची किंग्स ने सबसे ज्यादा तीन मैच जीते

अभी तक हुए मैचों में बाबर आजम की टीम कराची किंग्स ने सबसे ज्यादा तीन मैच जीते हैं। वह छह अंकों के साथ अंकतालिका में पहले पायदान पर हैं। पेशावर जालमी छह अंकों के साथ दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड (6 अंक) तीसरे, लाहौर कलंदर्स (6 अंक) चौथे, मुल्तान सुल्तान्स (2 अंक) पांचवें और क्वेटा ग्लेडिएटर्स (2 अंक) छठे स्थान पर हैं।

लाल बजरी के बादशाह नडाल का शानदार आगाज

जोकोविच को भी मिली आसान जीत

पेरिस। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने दबदबे के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में जीत दर्ज करके अपने अभियान की शुरुआत की। फ्रेंच ओपन में अपने 14वें खिताब और रिकार्ड 21वें ग्रैंडस्लैम खिताब की कवायद में लगे नडाल ने पहले दौर के मैच में आस्ट्रेलिया के 21 वर्षीय खिलाड़ी अलेक्सी पोपिरिन को 6-3, 6-2, 7-6 (3) से हराया।

इस तरह से उन्होंने रोलां गैरां में लगातार 26 सेट जीत लिये हैं। इनमें डोमिनिक थीम के खिलाफ 2019 के फाइनल के आखिरी दो सेट तथा 2020 के सात मैचों में सभी 21 सेट में जीत शामिल हैं। कोविड-19 के कारण पिछले साल फ्रेंच ओपन सितंबर-अक्टूबर में खेला गया था।

नडाल ने जीत के बाद कहा, मैं चोट को लेकर थोड़ा डरा हुआ था लेकिन यह अतीत की बात है। इस बार सब कुछ अधिक सहज है। नडाल तीसरे सेट में 5-2 से पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उनके अनुभव के सामने पोपिरिन की एक नहीं चली। नडाल ने इस बीच आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को गलतियां करने के लिये मजबूर किया।

जोकोविच को मिली आसान जीत

फ्रेंच ओपन ने रैंकिंग के आधार पर वरीयता तय की है और इसलिए नडाल को तीसरी वरीयता हासिल है। नोवाक जोकोविच को पहली जबकि दानिल मेदवेदेव को दूसरी वरीयता प्राप्त है। जोकोविच ने मंगलवार की रात को टेनिस सैंडग्रेन को दो घंटे से भी कम समय में 6-2, 6-4, 6-2 से हराया। जोकोविच ने छह ब्रेक प्वाइंट बचाये और 33 विनर्स लगाये।

महिलाओं में शीर्ष रैंकिंग की ऐश बार्टी ने तीन सेट तक जूझने के बाद अमेरिका की बर्नार्डा पेरा को 6-4, 3-6, 6-2 से पराजित किया। दो बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा एड़ी की चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गयी जबकि पुरुष वर्ग में सातवीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रूबलेव को पांच सेट में हार का सामना करना पड़ा।

बीसीसीआई पर जल्द फैसला लेने का दबाव, आईसीसी ने दिया इतना वक्त

नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में जल्द

अंतिम फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीसीसीआई को इसी साल भारत में टी-20 विश्वकप का आयोजन करना है मगर कोरोना महामारी के कारण अभी तक बोर्ड इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं ले सका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हुई बैठक में भारत को इस बारे में 28 जून तक फैसला लेने को कहा गया है। विश्व कप का आयोजन इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। इसलिए आईसीसी अब विश्वकप की तैयारियों को लेकर चिंतित है।

28 जून तक लेना होगा अंतिम फैसला

दुबई में हुई बैठक में भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बीसीसीआई की ओर से देश में कोरोना महामारी की दलील दी गई जिस पर आईसीसी की ओर से बीसीसीआई को 28 जून तक फैसला लेने का वक्त दिया गया। विश्व कप के आयोजन के संबंध में 28 तारीख तक बीसीसीआई को फैसले की जानकारी आईसीसी को देनी होगी। बीसीसीआई की 28 मई को हुई बैठक में भी टी20 वर्ल्ड कप पर इस महीने के आखिर तक कोई फैसला लेने की बात कही गई थी।

आईपीएल पर कोरोना की मार

बीसीसीआई ने काफी तैयारियों के बाद देश में आईपीएल के 14वें सीजन का आयोजन किया था मगर बायो बबल के बावजूद कई खिलाड़ियों के कोरोना के संक्रमित हो जाने के कारण आखिरकार इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। अभी टूर्नामेंट के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं। अब इसका आयोजन सितंबर-अक्टूबर के दौरान यूएई में किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि 18 सितंबर से टूर्नामेंट की शुरूआत के बाद 10 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा।

आईपीएल को स्थगित किए जाने के कारण बाकी बचे मुकाबलों की चमक फीकी भी पड़ सकती है क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ी बाकी बचे मैचों में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने दो दिग्गज खिलाड़ियों शाकिब अल हसन और मुस्ताफिजुर रहमान को एनओसी देने से इनकार कर दिया है।

यूरोपीय निशानेबाजी चैंपियनशिप: मनु भाकर और राही का 25 मीटर पिस्टल वर्ग एमक्यूएस में शानदार प्रदर्शन

ओसियेक । टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकीं भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और राही सरनोबत ने यहां यूरोपीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल वर्ग के न्यूनतम क्वालिफिकेशन स्कोर (एमक्यूएस) में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों ने सात निशानेबाजों के बीच उम्दा प्रदर्शन किया। मनु ने 587 का स्कोर करके नियमित और एमक्यूएस के बीच चौथा स्थान हासिल किया जबकि राही ने 584 का स्कोर करके छठा स्थान पाया। दोनों ओवरऑल आठवें स्थान पर थी। भारत का 13 सदस्यीय ओलंपिक पिस्टल और राइफल दल क्रोएशिया में अभ्यास सह प्रतिस्पर्धा दौरे पर है। वे आमंत्रित मेहमान के तौर पर ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं के एमक्यूएस दौर में भाग ले रहे हैं। इसमें निशानेबाज का स्कोर को दर्ज करना होता है लेकिन वे पदक दौड़ में शामिल नहीं होते।

फ्रेंच ओपन: बोपन्ना और कुगोर की जोड़ी दूसरे दौर में

पेरिस। भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के फ्रेंको कुगोर की जोड़ी फ्रेंच ओपन युगल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गई। उन्होंने जॉर्जिया के निकोलोज बासिलाश्विली और जर्मनी के आंद्रे बेजेमैन को सीधे सेटों में हराया। बोपन्ना और कुगोर ने एक घंटे और एक मिनट तक चले मैच में 6-4, 6-2 से जीत दर्ज की। बोपन्ना और कुगोर ने पहले सेट में प्रतिद्वंद्वी की सर्विस एक बार और दूसरे में दो बार तोड़ी। अब उनका सामना अमेरिका के निकोलस मुनरो और फ्रांसिस टियाफो तथा आठवीं वरीयता प्राप्त ब्राजील के मार्शेलो मेलो और पोलैंड के लुकाज कुबोत के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

लॉकडाउन बना रोड़ा: शरत-मनिका की तैयारियों का साफ नहीं हो रहा रास्ता

नई दिल्ली। विश्व नंबर पांच कोरियाई जोड़ी को हराकर मिश्रित युगल में ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली भारतीय जोड़ी अचिंत्य शरत कमल और मनिका बत्रा की एक साथ तैयारियों का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 20 जून से इंदौर में शिविर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लॉकडाउन के चलते मंजूरी नहीं मिल पा रही है।

साई सेंटर तैयार होता तो लग जाता शिविर

शरत, जी सथियन, मनिका, सुर्तीथा मुखर्जी के ओलंपिक क्वालिफाई करने के बावजूद लंबे समय से टेबल टेनिस खिलाड़ियों का ओलंपिक शिविर नहीं लगा है। इसका मुख्य कारण किसी भी साई सेंटर में ओलंपिक स्तर की टेबल टेनिस की सुविधाएं नहीं होना है। एक-दो वर्ष पहले तक एनआईएस पटियाला में टेबल टेनिस का शिविर लगता था, लेकिन वहां टेबल टेनिस का हॉल खत्म कर साई सेंटर बंगलूरू में हॉल स्थापित करने का फैसला लिया गया, लेकिन बंगलूरू में तैयारियां पूरी नहीं की जा सकी हैं। जिसके चलते साई सेंटर में टेबल टेनिस की तैयारियां नहीं हो पा रही हैं।

टीटीएफआई साई के सहयोग से अपने स्तर पर इंदौर, सोनीपत में शिविर लगाती रही है। इस बार भी उसकी योजना इंदौर के अभय प्रशाल में शिविर लगानी की थी लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे किसी शहर में शिविर लगाने की मंजूरी नहीं मिल रही है। टीटीएफआई इंतजार कर रहा है कि किसी तरह इंदौर से लॉकडाउन हटे तो उन्हें तैयारियों की मंजूरी मिल जाए। इस वक्त अगर साई सेंटर में शिविर लगा होता तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। चारों टेबल टेनिस खिलाड़ी इस वक्त अपने-अपने शहरों में तैयारियां कर रहे हैं। शरत ने तैयारियों में आ रही दिक्कतों के कारण डेनमार्क जाने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन उन्हें कोरोना के चलते भारत पर लगे प्रतिबंधों के कारण वीजा ही नहीं मिला। जिसके चलते वह चेन्नई में ही फंस गए हैं और मनिका पुणे में तैयारी कर रही हैं। सथियन भी चेन्नई में और सुर्तीथा कोलकाता में सौम्यजीत रॉय की अकादमी में तैयारियां कर रही हैं।

नियुक्ति: अमोल मजूमदार बने मुंबई के नए कोच, जाफर सहित नौ दिग्गजों को छोड़ा पीछे

बेंगलुरू। रेलू क्रिकेट के दिग्गज अमोल मजूमदार मुंबई (घरेलू सत्र 2021-22 के लिए) के नए कोच होंगे। विनोद कांबली, नीलेश कुलकर्णी और जतिन परांजपे की क्रिकेट सुधार समिति (सीआईसी) ने मजूमदार के नाम पर मुहर लगाई। मजूमदार रमेश पोवार की जगह लेंगे, जिन्हें भारत की सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि सीआईसी ने इस पद के लिए नौ उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें वसीम जाफर, साइराज बहुतले जैसे दिग्गज शामिल थे।

मुंबई के मुख्य कोच पद के लिए घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर, अमोल मजूमदार और पूर्व लेग स्पिनर साईराज बहुतुले ने आवेदन किया था। इनके अलावा मुंबई के मुख्य कोच पद के लिए जो अन्य लोगों ने आवेदन किया था, उनमें पूर्व कीपर-बल्लेबाज सुलक्षणन कुलकर्णी, तेज गेंदबाज प्रदीप सुंदरराम, नंदन फडनीस, उमेश पटवाल और विनोद राघवन शामिल थे। मुंबई के कोच पद की दौड़ में मजूमदार को चार महीने पहले पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर पोवार ने पछाड़ा था, जिनके मार्गदर्शन में मुंबई ने पिछले सत्र में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता लेकिन भारतीय टीम के साथ जुड़ने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। गौरतलब है कि मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने बीते दिनों सीनियर पुरुष टीम के कोच पद के लिए 50 प्रथम श्रेणी मैचों की पात्रता मानदंड के साथ आवेदन मांगे थे। बता दें कि मजुमदार मुंबई के पूर्व कप्तान हैं और उनकी कप्तानी में टीम प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी जीती है। मजूमदार ने 1993 से 2013 के बीच 171 प्रथम श्रेणी मैचों में 11167 रन बनाए।

ओलंपिक डायरी: ओलंपिक को लेकर सस्पेंस बरकरार, मैच खेलने के लिए पहली टीम पहुंची टोक्यो

टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक सॉफ्टबॉल टीम यहां पहुंच गई। यह ओलंपिक के लिए जापान पहुंचने वाली किसी देश की पहली टीम है। टीम उत्तरी टोक्यो स्थित ओटा सिटी में शिविर लगाएगी। कोविड-19 के कारण टीम ज्यादा मैचों में हिस्सा नहीं ले पाई है। जापान में तैयारी से उसे मौसम के अनुकूल होने में भी मदद मिलेगी। टीम को उद्घाटन समारोह से दो दिन पहले मेजबान जापान के साथ पहला मैच खेलना है।

विदेश से पहली टीम ऐसे समय में पहुंची है जब 23 जुलाई से होने वाले ओलंपिक से पहले जापान की जनता कोरोना संक्रमण के चलते खेलों को

आगे खिसकाने या रद्द करने की मांग कर रही है। विदेश से दर्शकों के आने पर रोक लगा रखी है। चर्चा तो यह भी है कि स्थानीय दर्शकों को भी शायद ही स्टेडियमों में प्रवेश मिले। टोक्यो सहित नौ क्षेत्रों में वायरस इमरजेंसी को बढ़ाकर 20 जून तक कर दिया गया है। ओलंपिक और पैरालंपिक के दौरान जापान में 200 से ज्यादा देशों के 15 हजार के करीब खिलाड़ी एकत्रित होंगे।

जापान में एथलीटों के टीके लगने शुरू

जापान ने ओलंपिक खेलों से जुड़े अपने एथलीटों के टीके लगाने शुरू कर दिया हैं। जापानी ओलंपिक समिति के अधिकारियों ने कहा कि 200 खिलाड़ियों को अभ्यास केंद्र में टीका लगाया गया। हालांकि इन खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। टीकाकरण के कवरेज पर भी रोक लगाई गई, इसके पीछे संभवत- जनता के विरोध का डर था। ओलंपिक समिति के अधिकारी मितसुगी ओगाटा ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के टीकाकरण से आम जनता को लगने वाले टीकाकरण पर असर नहीं पड़ेगा। खिलाड़ियों के टीकाकरण का जिम्मा अलग संस्था को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कह चुकी है कि ओलंपिक में भाग लेने के लिए टीकाकरण जरूरी नहीं है लेकिन कोरोना के दौर में यह सुरक्षित आयोजन के उपायों में शामिल है।

ओसाका पर दो भागों में बंटा क्रिकेट जगत

मिताली ने कहा- महिला क्रिकेटर्स को मीडिया सपोर्ट की जरूरत; कैफ बोले- मानसिक शांति के लिए दूर रहने की छूट मिले

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका का समर्थन किया है। ओसाका ने मेंटल हेल्थ की वजह से फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। उन पर मीडिया से बातचीत नहीं करने को लेकर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

कैफ ने इस पर कहा कि अगर खिलाड़ियों को मानसिक शांति के लिए मीडिया से दूर रहना सही लगता है, तो उन्हें इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज ने कहा है कि महिला खिलाड़ियों को मीडिया सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कभी इससे परहेज नहीं किया।

कैफ ने मेंटल हेल्थ को लेकर क्या कहा?

कैफ ने कहा- हम स्पोर्ट्स में मेंटल हेल्थ को लेकर काफी बातचीत करते हैं। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इसके मायने और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए टीम मेट नहीं होता। क्रिकेट में किसी सीनियर प्लेयर को उस खिलाड़ी की जगह बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है। पर टेनिस में यह पॉसिबल नहीं है। हमें थोड़ा उदार बनना होगा। खिलाड़ियों को मीडिया से बात नहीं करने की छूट नहीं देनी होगी।

मिताली ने ओसाका को लेकर क्या कहा?:मिताली ने कहा- मुझे पता है कि क्वारैंटाइन में रहना कितना मुश्किल होता है। पर टूर्नामेंट में खेलने के दौरान इसका पता नहीं चल पाता। व्यक्तिगत तौर पर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जाऊं। जिस स्थिति में महिला क्रिकेट है, उन्हें फिलहाल मीडिया सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए हम खेल को प्रमोट करते हैं।